fo"k; lwph

कमल संदेश

लोकसभा चुनाव २००९

राजनाथ सिंह ने भरा पर्चा...... 4
एनडीए एकमात्र विकल्प......... 5
धर्मगुरुओं को पत्र.................... 7
कीचड़ उछालने की राजनीति.. 9
डा. अम्बेडकर की उपेक्षा......... 11
काला धन वापस लाएंगे........... 13
अटलजी की अपील................ 17
राजग ही दिशा देने में सक्षम. 24
कांग्रेस में दम नहीं................. 25
भय–भूख कांग्रेस की उपलब्धि. 26

लेख

आम आदमी पूछता है
प्रशांत गोयल.................... 15
सीबीआई राजनीति का खिलौना
शिवशक्ति बक्शी.............. 23

साक्षात्कार

श्री लालकृष्ण आडवाणी........... 16

अन्य

आधारभूत ढांचा दृष्टिकोण–पत्र. 19
कांग्रेस पार्टी मकड़जाल में...... 21
दिल्ली....................................... 28

सम्पादक
çHkkr >k] lkaln

सम्पादक मंडल
lR;iky
d- d- 'kek
lath. dekj flUgk
jkeu;u flag

पृष्ठ संयोजन
/kesUæ dk'ky

सम्पर्क
Mk- eqdthZ Lefr U;kl
ihih&66] lqcze.;e Hkkjrh ekxZ
ubZ fnYyh&110003
Qksu ua- +91¼11½&23381428
QSDl % +91¼11½&23387887

सदस्यता शुल्क
okf"kZd 100#- | f=okf"kZd 250#-

e-mail address
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

अवसरवादी दलों को सबक सिखाएं

t नता यूपीए और कांग्रेस के विरोध में है। वैसे तो यूपीए के प्रत्येक घटक स्वयं एक–दूसरे के विरोध में आ खड़े हुए हैं। राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, यह कहावत स्वतः चरितार्थ हो रही है। सच में यूपीए में 'कुछ भी' हो रहा है। कुर्सी के फेविकोल से चिपके, चिपकू दल के राजनेता 'चाहे वो लालू हों या मुलायम या फिर पासवान, इस समय तीनों का दिमाग आसमान पर है। सदैव 'अलग रहने वालों को 'कुर्सी' ने एक मेज पर ला दिया। मुझे नहीं पता कि पुराने तीनों समाजवादियों की यह तिकड़ी शायद जनता को मूर्ख समझती है। जनता भलीभांति उन कारणों को जानती है कि ये तीनों क्यों एक हुए हैं। 'स्वार्थ' एवं 'अवसरवाद' के साथ–साथ मौकापरस्त राजनीति के जनक कहे जाने वाले इन तीनों नेताओं को जनता ने सबक सिखाने की ठान रखी है। भारतीय राजनीति में राजनैतिक तौर पर प्रदूषण फैलाने वालों में तीनों प्रदूषित राजनीतिज्ञों को इस चुनाव में आटे–दाल का भाव समझ में आ रहा है। वैसे तो लालू भी बिहार में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी नियति इतनी खराब है कि उनके साले साधु यादव ने ही उनके खिलाफ बगावत का स्वर बुलंद कर दिया है। साधु यादव 'जीजा' के खिलाफ हो गए और राहुल के करीब हो गए। दलबदलू को कांग्रेस ने टिकट देकर राजनैतिक तौर पर लालू से साधु को विमुख करने का रास्ता स्वतः साफ कर दिया।

भाई मुलायम सिंह तो अपने दोस्त श्री अमर सिंह के रिमोट से निकल ही नहीं पाए। जयाप्रदा और आजम खां का विवाद मुलायम सिंह सुलझा नहीं पा रहे हैं। पासवानजी तो शरद पवार की भी जय और मनमोहन सिंह की भी जय में लगे हुए हैं। जो कुर्सी दे दे 'उसकी जय' बोलने वाले पासवान भी इस समय उतार पर हैं। ये न दलित हितैषी हैं और न स्वयं दलित हैं। पासवान और मायावती को स्वयं को दलित नेता कहकर दलितों का अपमान करते हैं। दलितों के नेता का ढोंग करने वाले ऐसे नेताओं के शरीर पर लाखों के जेवरात स्वयं इस बात की गवाही देते है कि ये दलितों के नाम पर बड़े लम्बरदार नेता हैं। इनका संघर्ष से कम सुविधाओं से ज्यादा वास्ता है।

राजनीति के नाम पर अपनी दुकान चलाने के लिए पिछले वर्ष विश्वास मत के दौरान सपा के अमर सिंह ने जो कुछ किया, क्या वह लोकतंत्र को लजाने वाली घटना नहीं थी। नोट तंत्र से लोकतंत्र का गला घोंटने वाली कांग्रेस और सपा की गलबहियां गाली में बदल चुकी है। अन्य छोटे–छोटे राजनैतिक दल जिनका कुकुरमुत्तों की तरह जीवन है, भी इस आशा में खड़े हैं कि कहीं उनकी लॉटरी लग गई तो लाखों के वारे–न्यारे हो जाएंगे।

कांग्रेस के पास अब न तो नीति बची है न सिद्धांत। न नेता बचे हैं न कार्यकर्ता। कांग्रेस में बचे हैं गिरोह। देश के सामने एक तीसरा मोर्चा भी वामपंथियों के सहयोग से लड़खड़ाते हुए भी दौड़ने का दावा कर रही है। दावा करने में क्या लगता है। अतः उनका दावा तब तक दावा कहलाएगा जबतक इनकी पोल नहीं खुलती। वामपंथियों ने भी अपने–अपने दलों को दुकान का रूप दे दिया है। वे हर समय 'बिकने को तैयार' की मुद्रा में खड़े पाए जाते हैं। इनके हाथ में एक हथियार सदैव रहता है 'क्या करें सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने और धर्मनिरपेक्षता को जीवित रखने के लिए' हम भाजपा छोड़कर किसी के साथ जा सकते हैं।

स्थिति ऐसी हो गई कि राजनीति के इन कुर्सी चिपकू नेताओं ने नीति और सिद्धांत को न केवल दफना दिया बल्कि उसकी अंत्येष्टि कर दी। एक मात्र भाजपा है जो अब तक अपनी नीति और सिद्धांतों के साथ साथ गठबंधन धर्म का पालन करते हुए घटक दलों के साथ चलने की क्षमता रखती है। आज आवश्यकता है स्वार्थी एवं अवसरवादी स्वभाव वाली कुकुरमुत्ते की तरह उग आए राजनैतिक दलों को सबक सिखाने का। आम भारतीय को ऐसा अवसर नहीं गंवाना चाहिए।■

देश को खुशहाल बनाएंगे : राजनाथ सिंह

गाजियाबाद स्थित हंस प्लाजा में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हवन कराने के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने 17 अप्रैल को गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से नामांकन–पत्र दाखिल किया।

इसके पश्चात् घंटाघर रामलीला मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में बढ़ रही महंगाई के लिए केंद्र में काबिज कांग्रेस सरकार का आर्थिक प्रबंधन व नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार जिम्मेदार है।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तब राजग सरकार ने पोखरन में परमाणु विस्फोट किया, जिससे कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाये लेकिन परिस्थिति अनुकूल न होने के कारण भी भाजपा की सरकार ने महंगाई नहीं बढ़ने दी। आज महंगाई चरम सीमा पर है।

उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा श्री लालकृष्ण आडवाणी को आरएसएस का गुलाम बताने पर एतराज जताते हुए कहा कि हम लोग तो आरएसएस के हैं, इसमें गुलामी जैसी बात कहां है। उनसे पूछा जाए कि क्या कांग्रेस एक परिवार की ही पार्टी बन कर रह गई है। इस प्रश्न पर उन्हें कैसी अनुभूति होगी, यह देखने व समझने की बात है।

श्री सिंह ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात देश पर पचास साल कांग्रेस का राज रहा जिसमें इन सरकारों ने केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। आज हमारे देश का लगभग सात करोड़ रूपया स्विटजरलैंड के बैंक खाते में है। यदि केवल यह पैसा भारत वापिस आ जाये तो देश विकासशील ही नहीं बल्कि विकसित देशों की गिनती में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार एनडीए की बनती है तो हम कूटनीतिक दवाब से पैसे को वापस देश में मंगाकर देश की खुशहाली में लगाएंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार से पहले कोई अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष भारत का दौरा नहीं करना चाहता था लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति क्लिंटन ने भारत की यात्रा की और संसार को भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था से अवगत कराया।

श्री सिंह ने कहा कि यदि केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो वे किसानों

के हित में न केवल भूमि अधिग्रहण संबंधी अधिनियम में संशोधन लाएंगे बल्कि जरूरी हुआ तो नया नियम भी बनवाने की कोशिश करेंगे ताकि स्वेच्छा से भूमि देने वाले किसानों को उनकी जमीनों का बाजार भाव मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा कि राजनीति में कांग्रेस ने जो कीचड़ उछालने का काम किया है वह बंद होना चाहिए। सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ–साथ उन्होंने बसपा मुखिया मायावती व सपा प्रमुख मुलायम सिंह को भी जमकर निशाना बनाया। उन्होंने जनता से कहा कि वे जनप्रतिनिधि बनने के लिए ही वोट नहीं मांग रहे , बल्कि आज भारत संकट में है और उसे बचाने के लिए वे वोट मांग रहे हैं।

इससे पूर्व चुनावी सभा में सभा में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद ने संसद पर हमले के साजिशकर्ता आतंकवादी अफजल गुरू को फांसी न देने पर कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य आज विकास की गति पकड़ चुका है। राज्य में 22 करोड़ परिवारों को आने वाले समय में केवल 2 रूपये किलो चावल मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मेजर जनरल श्री भुवन चन्द खंडूरी ने कहा कि भाजपा ही एक भय और भ्रष्टाचारमुक्त समाज दे सकती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री रमापति त्रिपाठी ने कहा कि राजनाथ सिंह के गाजियाबाद से उम्मीदवार होने पर आज गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया।

पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखवीर सिंह बादल ने अपने उद्बोधन में राजनाथ सिंह को किसानों का बड़ा नेता बताया। उन्होंने कहा कि 1984 में हुए दंगों में सिखों के नरसंहार व बर्बादी के लिए जिम्मेदार कांग्रेस नेताओं को सजा दिलाने की बजाय उन्हें मंत्री व सांसद बनाने का काम कर रही है। सिख समाज कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। सभा को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना, विधानसभा में विपक्ष के उपनेता हुकुम सिंह, भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष एवं सांसद कुसुम राय, जनता दल(यू) के राष्ट्रीय महामंत्री के सी त्यागी समेत दर्जनों नेताओं ने संबोधत किया। मंचासीन मुख्य नेताओं में मेयर दमयंती गोयल, विधायक सुनील शर्मा, रालोद के प्रदेश महासचिव ब्रजपाल तेवतिया, भाजपा महानगर अध्यक्ष अशोक मोंगा, नरेंद्र गुजराल आदि मौजूद थे। मंच संचालन विजय मोहन ने किया। ■

एनडीए एकमात्र विकल्प : लालकृष्ण आडवाणी

तिरूवनन्तपुरम में 13 अप्रैल, 2009 को संवाददाता सम्मेलन में श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा जारी वक्तव्य

श्रीमती सोनिया गांधी का यह बयान कि ''हमें भारत में आ रहे विदेशी आतंकवादियों की अपेक्षा अपने ही देश के भीतर के लोगों से ज्यादा खतरा है'' खतरनाक और गैर–जिम्मेदाराना है। भारतीय जनता पार्टी इस निन्दात्मक वक्तव्य के लिए उनसे क्षमायाचना की मांग करती है।

मेरा ध्यान कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा खूंटी झारखंड में 11 अप्रैल, 2009 को अपनी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित एक चुनावी रैली में दिए गए अत्यंत आपत्तिजनक भाषण की ओर दिलाया गया है।

दी स्टेट्समैन समाचार-पत्र में दी गई रिपोर्टः

कांग्रेस अध्यक्ष तथा रायबरेली से सांसद श्रीमती सोनिया गांधी ने खूंटी, झारखंड में आज एक चुनावी रैली में भारतीय जनता पार्टी पर अप्रत्यक्ष प्रहार किया लेकिन पार्टी का नाम लेते–लेते अचानक रूक गईं....... ....'' हमें भारत में घुस रहे विदेशी आतंकवादियों से ज्यादा अपने ही देश के भीतर के लोगों से अधिक खतरा है। देश के भीतर ऐसे लोग हैं, जो हमेशा धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, भारत को आतंकवाद की अपेक्षा साम्प्रदायिकता से ज्यादा खतरा है। श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा, जो पार्टियां देशप्रेम के मुखौटे पहनकर धर्म की संकुचित आड़ में जनता को बांटना चाहती है वे ही देश को भीतर से खोखला कर रही हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट :

''श्रीमती सोनिया गांधी ने किसी पार्टी अथवा नेता का नाम लिए बगैर कहा कि देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं।'' उन्होंने कहा, ''इन लोगों ने देशभक्ति के मुखौटे पहन रखे हैं लेकिन वे तुच्छ राजनीति का लाभ उठाने के लिए वास्तव में राष्ट्र को कमजोर बनाने में लगे हुए हैं।'' उन्होंने आगे यह भी कहा कि ''देश को बाहर से आने वाले आतंकवादियों का उतना खतरा नहीं है जितना कि देश के भीतर के लोगों से।''

मैं कांग्रेस अध्यक्ष की इस सोच से भौंचक्का रह गया हूं कि ''हमें भारत में आने वाले विदेशी आतंकवादियों की अपेक्षा अपने देश के भीतर के लोगों से ज्यादा खतरा है।'' अथवा यह कि देश को बाहर से आने वाले आतंकवादियों से खतरा नहीं है बल्कि देश के भीतर से ही खतरा पैदा हो रहा है।''

मुझे यह पक्का यकीन है कि कांग्रेस की हार निश्चित है। केन्द्र में एक ऐसी सरकार जो सुशासन, विकास और सुरक्षा के सिद्धांतों के प्रति दृढ़–प्रतिज्ञ हो, बनाने के लिए मतदाता के समक्ष भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन ही एकमात्र विकल्प है।

मैंने सन् 1952 के प्रथम आम चुनावों से ही सभी कांग्रेस अध्यक्षों को देखा है। उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि भारत की सुरक्षा को बाहरी लोगों से ज्यादा देश के भीतर से अधिक खतरा पैदा हो रहा है।

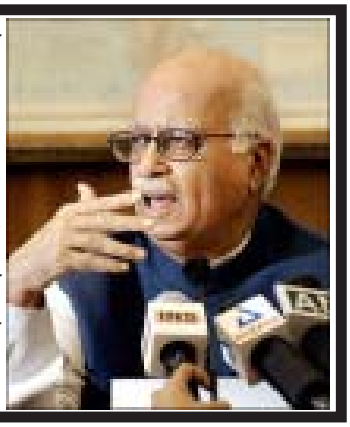

सन् 1980 के दशक के शुरू में भारत में आतंकवाद की शुरूआत से ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य कई दलों सहित भारत के राजनीतिक वर्ग में इस बात पर व्यापक आम–सहमति थी कि इस खतरे का स्रोत सीमापार है और वास्तव में यह खतरा पाकिस्तान द्वारा '''प्रोक्सी वार'' के रूप में है। इस बात पर भी व्यापक सहमति थी कि पाकिस्तान ने आई.एस.आई. के माध्यम से भारत के विरूद्ध ''प्रोक्सी वार'' का सहारा लिया हुआ है क्योंकि यह सन् 1948, 1965 और 1971 के परम्परागत युद्धों के जरिए अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा है। भारत के विभिन्न स्थानों पर बम–विस्फोटों के अलावा, पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा दो युद्ध जैसे आतंकवादी हमले किए गए जिनमें 13 दिसम्बर, 2001 को भारतीय संसद को निशाना बनाया गया और गतवर्ष 26 नवम्बर को मुम्बई में दो भयंकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया।

वास्तव में, 26 नवम्बर की आतंकवादी घटना के बाद मेरी पार्टी ने यूपीए सरकार को उस समय समर्थन दिया जब इसने वर्ष 2004 में पोटा को निरस्त करने के बाद काफी देर से दो

आतंक–विरोधी विधान संसद में पेश किए। मैंने संसद में बोलते हुए कहा था कि भारत के सम्पूर्ण राजनीतिक वर्ग को अपने आंतरिक मतभेद भुलाकर बाहरी खतरे का मुकाबला करने में एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए।

कोई भी राष्ट्रवादी भारतीय सीमापार आतंकवाद के खतरे को कभी भी कम महत्व नहीं देगा और यह नहीं कहेगा कि हमारे देश के भीतर के लोगों से ही ज्यादा खतरा पैदा हो रहा है। यह स्पष्ट है कि सोनियाजी इस सम्बन्ध में अपने वरिष्ठ पार्टी नेताओं की परम्परा से भी अनभिज्ञ हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री ने सन् 1962 तथा 1965 की लड़ाइयों के समय राष्ट्रीय प्रयासों में जनसंघ तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान की सराहना की थी। पंडित जी ने वास्तव में 1963 की गणतंत्र दिवस परेड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को शामिल किया था।

हालांकि श्रीमती गांधी ने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया था लेकिन यह स्पष्ट है कि कांग्रेस अध्यक्ष न केवल हमारी देशभक्ति पर ही प्रश्नचिह्न खड़ा करते हुए बल्कि एक गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमले कर रही थीं। उन्हें इस निन्दात्मक वक्तव्य के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे इस मुद्दे पर बहस में हमारे साथ हिस्सा लेकर राष्ट्र को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी बाहर से आने वाले आतंकवादियों की अपेक्षा भारत की सुरक्षा और एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर रही है। भारत की जनता को फैसला करने दें।

यदि वे बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे इस तरह की गैर–जिम्मेदाराना बयानबाजी करने से बचें। मुझे याद आता है कि 2004 के संसदीय चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने तथाकथित ''कॉफिनगेट'' मुद्दा उछाला था और गंभीर आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन सरकार ने भारतीय सेना के शहीदों के लिए ताबूतों की खरीद में पैसा बनाया। यूपीए सरकार अपने पांच वर्षों के कार्यकाल में इस आरोप को साबित नहीं कर पाई है।

कांग्रेस दूसरी पारी के कार्यकाल की नहीं बल्कि सबक सिखाए जाने की हकदार है। तीसरे और चौथे मोर्चे प्रासंगिक नहीं है; भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन ही एकमात्र विकल्प है

अब से तीन दिनों बाद भारतीय मतदाता 15वीं लोकसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान में हिस्सा लेंगे। अब से ठीक एक महीने बाद 13 मई को पांचवें और आखिरी चरण का मतदान पूरा होगा। दिन–प्रतिदिन यह साफ होता जा रहा है कि नई दिल्ली में अगली सरकार बनाने के लिए मुख्य मुकाबला भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (जोकि राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र चुनाव–पूर्व मजबूत गठबन्धन है) और कांग्रेस (जिसका अपना यूपीए गठबन्धन ही टूट गया है) के बीच है।

जहां तक तीसरे मोर्चा और चौथे मोर्चा के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने का सम्बन्ध है, ये तथाकथित मोर्चे अप्रसांगिक हैं। वे अवसरवादी मंच हैं, जिनका न तो कोई साझा मंच है और न ही कोई साझा नेता। सीपीआई (एम) अपनी बढ़ती अप्रसांगिकता को छिपाने के लिए दोनों में सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। भारत की जनता जानती है कि तीसरे अथवा चौथे मोर्चे की सरकार देश के लिए खतरनाक होगी।

जहां तक तीसरे मोर्चा और चौथे मोर्चा के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने का सम्बन्ध है, ये तथाकथित मोर्चे अप्रसांगिक हैं। वे अवसरवादी मंच हैं, जिनका न तो कोई साझा मंच है और न ही कोई साझा नेता। सीपीआई (एम) अपनी बढ़ती अप्रसांगिकता को छिपाने के लिए दोनों में सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। भारत की जनता जानती है कि तीसरे अथवा चौथे मोर्चे की सरकार देश के लिए खतरनाक होगी।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन और इसके विरोधियों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। हमारे घटक के सहयोगी दलों का किसी भी स्थान पर एक दूसरे से मुकाबला नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, वे दल जो अभी भी यूपीए सरकार का हिस्सा बने हुए हैं, एक दूसरे के विरूद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। किसी ने खुलकर कहा है कि डा0 मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं न कि अन्य दलों के। इस गठबन्धन की कोई पार्टी तीसरे मोर्चे की पार्टियों के साथ चुनाव मंच में शामिल हो गई है।

यूपीए सरकार में इस तरह की अव्यवस्था पैदा हो गई है कि कांग्रेस अपने गठबंधन को एकजुट नहीं रख पाई है और यह विफलता मुख्यतः इसलिए है क्योंकि इसके सहयोगी दल सोचते हैं कि कांग्रेस भरोसा करने लायक पार्टी नहीं है।

कांग्रेस की दो तरीके से मजबूरी है। पहली, अनेक मोर्चों (मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा और आतंकवाद को रोकने में विफलता) पर यूपीए सरकार की विफलताओं और विश्वासघातों के कारण इस पर ''एंटी–इन्कम्बेंसी'' का भारी बोझ है। दूसरे, इसने अपने गठबन्धन के सहयोगी दलों का विश्वास खो दिया है।

पहली मजबूरी से कांग्रेस को देशभर की जनता के रोष का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी मजबूरी से कांग्रेस को अपने गठबन्धन की सहयोगी पार्टियों के अपने प्रति अविश्वास की भावना का सामना करना पड़ा है। देश में इस तरह की भावना पनप रही है कि कांग्रेस पार्टी दूसरे कार्यकाल में सत्ता में आने की बजाए सबक सिखाए जाने के लायक है। इसलिए, मुझे यह पक्का यकीन है कि कांग्रेस की हार निश्चित है। केन्द्र में एक ऐसी सरकार जो सुशासन, विकास और सुरक्षा के सिद्धांतों के प्रति दृढ़–प्रतिज्ञ हो, बनाने के लिए मतदाता के समक्ष भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन ही एकमात्र विकल्प है। मैं केरल सहित देश के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन में शामिल इसके सहयोगी दलों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश दें ताकि राष्ट्र के समक्ष खड़ी आंतरिक और बाह्य, दोनों चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए नई दिल्ली में एक सक्षम, सशक्त और स्थिर सरकार बन सके। ■

आदर्श शासन व्यवस्था 'रामराज्य' में निहित : लालकृष्ण आडवाणी

गत 7 अप्रैल को राजग की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री लालकृष्ण आडवाणी ने देश के धर्मगुरूओं को पत्र लिखकर उनसे उचित मार्गदर्शन प्रदान करने का निवेदन किया और उन्हें आश्वस्त किया कि अगर देश ने हमें चुना तो एनडीए सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रखरता से पहल करेगी। हम इस पत्र का पूरा पाठ यहां प्रकाशित कर रहे हैं:–

vkज जबकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एनडीए) मिलकर 15वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको यह पत्र लिखते हुए मैं अपने आपको बहुत ही प्रसन्न व गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और साथ ही आपका आशीर्वाद भी चाहता हूं। मेरी पार्टी और गठबन्धन इन चुनावों में सुशासन, विकास और सुरक्षा की वचनबद्धता के साथ सरकार बनाने हेतु जनता से समर्थन चाहते हैं। अगर हमें जनादेश मिला तो हमारा प्राथमिक लक्ष्य रहेगा कि हम एक ईमानदार तथा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएं जोकि राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि प्राथमिकता दे व आम आदमी की उन्नति के लिए काम करे। विशेष रूप से वे जोकि आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।

आज देश के जो हालात हैं वे आपके सामने ही हैं। आप स्वयं ज्ञाता हैं और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कुछ मुद्दों की ओर आपका ध्यान दिलाना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। सीमापार से संचालित हो रही आतंकवादी घटनाओं ने देश की सुरक्षा को तार–तार कर दिया है। पिछले पांच वर्षों में अगर इराक को छोड़ दें तो अकेले भारत में ही आतंकवाद इतनी जानों को लील गया है जितना कि पूरे विश्व में हुई आतंकवादी घटनाओं में गई जानों से भी अधिक है। बंगलादेशियों की अवैध घुसपैठ निर्बाध रूप से जारी है। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी इस अनवरत 'बाहरी आक्रमण' घुसपैठ पर कई बार सरकार को चेताया है। भारत चारों तरफ से अस्थिर राजनैतिक परिस्थितियों को झेल रहे देशों से घिरा हुआ है। भारत विरोधी ताकतें चारों ओर से सिर उठा रहीं हैं, विशेष रूप से पाकिस्तान में पनप रहे हालात भारत विरोधी वातावरण को और मजबूत बना रहे हैं। यहां तक कि नेपाल और श्रीलंका जोकि बहुत लम्बे से हमारे स्वाभाविक मित्र हैं, उनसे भी रिश्तों में तनाव शुरू हो गया है।

अर्थव्यवस्था के कुप्रबन्धन के चलते पिछले पांच वर्षों में आम आदमी की दुर्गति ही हुई है। आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के बेतहाशा बढ़े दामों ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया है। स्टॉक मार्केट के उतार–चढ़ाव पर टिकी आर्थिक उन्नति का बुलबुला फूट चुका है, जिसके चलते पूरा देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। देश में पहले से व्याप्त बेराजगारी से तो निजात मिली नहीं थी कि बड़े पैमाने पर लगी लगाई नौकरियां छूटने से देश की जनता, विशेषकर युवाओं, पर तो मानों पहाड़ ही टूट पड़ा है। आज देश का युवा वर्ग अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त है। पूरे देश का पेट भरने वाला अन्नदाता यानि हमारे किसान भाइयों द्वारा हजारों की संख्या में की गई आत्महत्याओं ने मुझे सबसे अधिक पीड़ा दी है और मेरा मन बहुत ही उद्वेलित हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी देश को इतना निराश नहीं देखा।

मेरी जीवनपर्यन्त यह मान्यता रही है कि राजनीति, शासन व अन्य राष्ट्रीय कार्यों का मार्गदर्शन उन आदर्शों से होना चाहिए जो गांधीजी द्वारा व्याख्या किए गए एक आदर्श राज्य शासन व्यवस्था यानि 'राम राज्य' में निहित है।

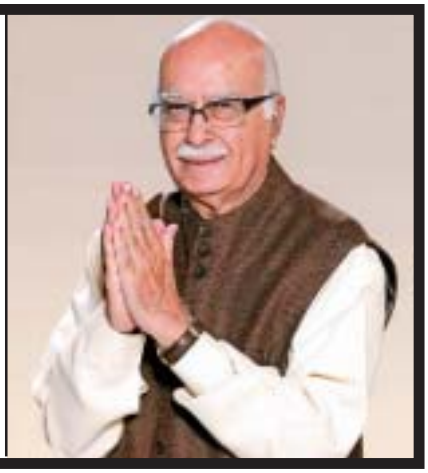

अगर देश ने हमें चुना तो एनडीए सरकार और मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हम यह प्रयास करें कि निराशा का यह वातावरण समाप्त हो तथा लोगों में आशा और विश्वास का भाव पैदा हो।

भारत एक धर्मनिष्ठ देश है। हमारे लोगों का धर्म में अटूट विश्वास है और अपने जीवन के हर निर्णय में आप जैसे धर्मगुरूओं और आध्यात्मिक गुरूओं का

मार्गदर्शन वे लोग अवश्य लेते हैं। ऐसा इसलिए है कि धर्म ने हमेशा ही हमारे देश व देशवासियों को सही दिशा दी है और इसका कल्याण ही किया है। धर्म

ने हमेशा ही हमारे देश व समाज के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का काम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान परिस्थितियों में आप सभी भारतवासियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और यह निराशा का माहौल समाप्त करने में आप अपनी महती भूमिका निभाएंगे।

हमारी योजनाएं देश की जनता के सामने एनडीए के घोषणा–पत्र के रूप में आएंगी किन्तु मैं इस पत्र के माध्यम से कुछ विशिष्ट आश्वासन आपको अवश्य देना चाहूंगा जोकि देशभर में चल रहे धार्मिक संस्थानों से सम्बन्धित हैं।

- मेरा यह सतत् प्रयत्न रहेगा कि देश के सामने आने वाली सभी चुनौतियों व गंभीर विषयों पर आप सभी धर्मगुरूओं व आध्यात्मिक गुरूओं से मार्गदर्शन व सलाह लूं। इसके लिए हम एक उचित सलाहकार संरचना बनाएंगे।
- देश के विभिन्न मतों–मतान्तरों की आध्यात्मिक विरासत के प्रति सरकारी उदासीनता को हम समाप्त करेंगे। दुर्भाग्य से पंथनिरपेक्षता के सच्चे आचरण व प्रचलन ने पिछले पांच वर्षों में धर्म विरोधी व नास्तिकता का रूप ले लिया है। पंथनिरपेक्षता को सच्चे अर्थों में अर्थात् 'सर्वपंथ समादर' के रूप में स्थापित करेंगे। हम अपेक्षा करेंगे कि सभी धार्मिक संस्थान राष्ट्र प्रेम व आध्यात्मिकता की भावना को देशवासियों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें ताकि एक ओजपूर्ण समाज का निर्माण हो सके।
- हम सभी धर्मों, मतों व संप्रदायों के तीर्थस्थलों के विकास व सौन्दर्यीकरण के लिए एक विशेष संस्था बनाएंगे ताकि माता वैष्णो देवी व तिरूमाला तिरूपति देवस्थानम् जैसी सुविधाएं उन्हें भी मिल सकें। इस राष्ट्रीय संस्था की अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए सभी तीर्थस्थलों की सुरक्षा को सर्वोच्च वरीयता दी जाएगी।
- अमरनाथ विवाद जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी।
- रामसेतु की रक्षा की जाएगी।
- गंगा व अन्य नदियों की सफाई को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
- गाय व गौवंश की रक्षा व उन्नयन के प्रति वचनबद्धता होगी।
- विदेशों से प्राप्त आर्थिक सहायता का सरकारी नियमों के अनुसार संचालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि उस धन का उसी मद में उपयोग हो जिसके निमित्त वह प्राप्त किया गया है तथा धर्मांतरण के लिए न हो।
- मैं जानता हूं कि धार्मिक संस्थाओं को सरकारी कार्यों विशेषतः आयकर में छूट की अवधि बढ़ाने आदि के कार्यों को निष्पादित करने में प्रायः मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अतः हमारी सरकार एक विशेष प्रकोष्ठ बनाएगी जोकि सभी धार्मिक संस्थाओं के कार्यों में उनकी सहायता करेगा।
- धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे सभी सामाजिक व राष्ट्र–निर्माण की दिशा में किए जा रहे कार्यों जैसे कि मिड डे मील, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक शिक्षा व अनाथों की सेवा आदि को केन्द्र सरकार का पूर्ण समर्थन मिलेगा।
- धार्मिक पर्यटन के विकास को उचित बढ़ावा दिया जाएगा।
- भारत की आध्यात्मिक व धार्मिक विरासत को दुनियाभर में प्रचारित व प्रसारित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जायेंगे।

मेरा यह सतत् प्रयत्न रहेगा कि देश के सामने आने वाली सभी चुनौतियों व गंभीर विषयों पर आप सभी धर्मगुरूओं व आध्यात्मिक गुरूओं से मार्गदर्शन व सलाह लूं। इसके लिए हम एक उचित सलाहकार संरचना बनाएंगे।

धर्मगुरू के रूप में आपने हमेशा सामाजिक व धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर शांति, अनुरूपता, एकता व भाइचारे के लिए ही काम किया है। मैं स्वयं भी इन सभी मूल्यों में निष्ठा रखता हूं। मेरी जीवनपर्यन्त यह मान्यता रही है कि राजनीति, शासन व अन्य राष्ट्रीय कार्यों का मार्गदर्शन उन आदर्शों से होना चाहिए जो गांधीजी द्वारा व्याख्या किए गए एक आदर्श राज्य शासन व्यवस्था यानि 'राम राज्य' में निहित है।

आज ऐसे विकट समय में जबकि हमारे देश की जनता एक निर्णायक बदलाव की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। मैं, आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन व समर्थन चाहता हूं। ■

कीचड़ उछालने की राजनीति बंद करने के लिए प्रधानमंत्री पहल करें : राजनाथ

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह द्वारा अप्रैल 15, 2009 को बैंगलूरू में जारी वक्तव्य

दिल्ली में संप्रग सरकार का शासनकाल अब लगभग समाप्त होने के निकट है। इस सरकार ने अपने पीछे प्रायः सभी मोर्चों पर विफलताओं की एक लम्बी सूची छोड़ी है। इन पांच वर्षों के दौरान देश को अनेक अभूतपूर्व संकटों का सामना करना पड़ा। केन्द्र में एक मजबूत इच्छाशक्ति वाली सरकार और दृढ–संकल्पी नेतृत्व के अभाव ने इस संकट को और अधिक गहरा कर दिया है।

प्रधानमंत्री को कभी भी किसी तरह के कलंकित करने वाले अभियान में वैयक्तिक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह स्वयं चुनाव अभियान के नाम पर की जा रही इन कीचड़ उछालने वाली करतूतों को बंद करने की पहल करेंगे।

गर्तोन्मुख संप्रग की तुलना में मजबूत होता राजग

भाजपा को किसी भी कीमत पर सत्ता से बाहर रखने की राजनीतिक विवशता के कारण संप्रग 2004 में अस्तित्व में आया। कोई भी ऐसा गठबंधन लम्बे समय तक बना नहीं रह सकता है जो घोर अवसरवादिता और अनुचित सौदेबाजियों को आधार बना कर किया जाता है। संप्रग के कुछ घटक दलों ने अधिक घास वाले चारागाहों को देख कर कांग्रेस से हाल ही में किनारा कर दिया है।

इससे गठबंधन का निर्वाह करने में कांग्रेस की अन्तर्निहित अक्षमता उजागर होती है। कांग्रेसनीत गठबंधन से बाहर जाने की इस अचानक फुर्ती का दूसरा कारण संप्रग सरकार का घटिया ट्रैक–रिकार्ड है। संप्रग की अक्षमता और निकम्मेपन के कारण इसके सहभागियों को उससे दूर जाने के लिए विवश होना पड़ा। इसमें कोई हैरत नहीं है कि संप्रग एक डूबता जहाज बन गया है, जिसकी डैक से उसके सहयोगी अपने आपको बचाने के लिए छलांग लगा रहे हैं।

इसके विपरीत भाजपा नीत राजग ने श्री अटल जी के कुशल नेतृत्व में गठबंधन के सहयोगियों को जोड़े रखने की कला में महारत हासिल कर ली है। अब श्री आडवाणी जी सबको साथ लेकर चलने की कला में पारंगत हो रहे हैं। राजग 2004 के लोकसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर जिस स्थिति में था, आज उससे कही बेहतर स्थिति में है क्योंकि भाजपा ने अपने अधिकांश प्रमुख सहभागियों को सफलतापूर्वक अपने साथ जोड़कर रखा है। राजग के सभी घटक दलों – अकाली दल, शिव सेना, जद(यू), एजीपी, आरएलडी और ईएनएलडी ने भाजपा और प्रधानमंत्री के पद के लिए इसके प्रत्याशी श्री लालकृष्ण आडवाणी को अपने बिना शर्त समर्थन का वचन दिया है।

राजग के बाहर भी हमारे अन्य कई मित्र हैं, जो चुनाव परिणाम घोषित हो जाने के बाद हमसे जुड़ जाएंगे। राजग अपनी उल्लेखनीय एकता, सामंजस्य और कठिन समय में दृढ़ता दर्शाने के कारण ही भारतीय राजनीति में एक सशक्त ताकत बनकर उभरा है।

इसमें एकमात्र अचरज की बात उड़ीसा में बीजद द्वारा किया गया विश्वासघात है। मूझे पूर्ण विश्वास है कि कर्नाटक के लोगों से सीख लेकर उड़ीसा के मतदाता भी बीजद के राजनीतिक विश्वासघात और अवसरवादिता को ठुकराकर उसको करारा सबक सिखाएंगे।

संप्रग की नीतियों से सबसे अधिक व्यथित आम आदमी

संप्रग शासनकाल के दौरान संप्रग की नीतियों ने सबसे भारी चोट आम आदमी को पहुंचाई है।

आज भारत की अर्थव्यवस्था मंदी के दबावों के नीचे कसक रही है। निर्यात घटकर निम्न धरातल पर आ गए है। छटनी के कारण लाखों कामगार अपना रोजगार गंवा बैठे हैं। देश में औद्योगिक उत्पादन नकारात्मक वृद्धि की मार झेल रहा है।

यद्यपि संप्रग सरकार मुद्रास्फीति को शून्य बिन्दु तक लाने की शेखी बघार रही है किन्तु यह इस तथ्य को छुपा रही है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य अभी भी बढ़ रहे हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक स्पष्ट रूप में दर्शा रहा है कि वास्तविक मुद्रास्फीति में अभी भी 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है।

सत्ता में आने के पश्चात् श्री आडवाणी के नेतृत्व में राजग सरकार देश में मूल्यों पर नियंत्रण करने और विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक समेकित तथा द्रुत कार्य योजना पर शिद्दत से काम करेगी।

कांग्रेस का कार्य निंदा और मिथ्यापवाद करना

कांग्रेसनीत संप्रग सरकार भाजपा और इसके नेतृत्व पर आधारहीन आरोप लगाते हुए एक मिथ्या अभियान चला रही है ताकि लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हट जाए।

भाजपा समकालीन मुद्दों – जैसे आतंकवाद, मूल्यवृद्धि, मंदी, सुरक्षा और विकास पर एक गंभीर बहस करना चाहती है किंतु कांग्रेस ऐसी बहस से दूर भागना चाहती है क्योंकि इन मोर्चों पर उसके पास कहने को कुछ नहीं है।

कांग्रेस पार्टी की ज्यादा दिलचस्पी विगतकालीन मुद्दों को उठाने में है। परसों प्रधानमंत्री जी ने कंधार का मुद्दा उठाया और भाजपा के विरूद्ध बेबुनियाद आरोप लगाने का प्रयास किया।

यह एक सर्वज्ञात सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी कंधार संकट के दौरान लोगों में घबराहट फैलाने की प्रमुख दोषी थी। इस पार्टी ने ही राजग सरकार के विरूद्ध आंदोलन को समर्थन दिया था, जिसमें अगवा किए गए वायुयान के सभी यात्रियों की तत्काल रिहाई की मांग की गई थी।

जब राजग सरकार ने इस संकट को सुलझाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई तब भी कांग्रेस पार्टी उसमें उपस्थित थी। किंतु इस पार्टी ने सभी यात्रियों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने के लिए आम सहमति के विरूद्ध एक शब्द भी विरोध में नहीं बोला था।

एक ओर कांग्रेस ने कंधार मुद्दे पर, जिसमें स्वयं कांग्रेस पार्टी लिए गए निर्णय में एक पक्षकार थी, रोष व्यक्त करती है, दूसरी ओर इसने चरारे–शरीफ में अपने स्वयं के कुकर्मों को पूरी तरह भूला दिया है जब कांग्रेस सरकार ने पांच खतरनाक आतंकवादियों को बच निकलने का सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित किया था वह भी इस स्थिति में जब कोई बंधक नहीं बनाया गया था।

जिन लोगों ने चरारे–शरीफ में आतंकवादियों के साथ बातचीत की थी। वे ही लोग हमारे ऊपर आज उस निर्णय का दोषारोपण कर रहे हैं, जो संकटकाल में लिया गया था। कांग्रेस पार्टी को उस पुरानी कहावत को ध्यान में रखने की जरूरत है कि कांच के घरों में रहने वाले लोगों को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।

कांग्रेस पार्टी का चुनावी एजेंडा भी विगतकालीन मुद्दों पर आधारित है। जबकि भाजपा का एजेंडा अधिक समसामयिक और प्रगतिशील है क्योंकि भाजपा का चुनावी नारा सुशासन, विकास और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर आधारित है।

एक स्वस्थ्य लोकतंत्र में विपक्षी नेताओं पर वैयक्तिक प्रहारों को कभी भी ठीक नहीं माना जा सकता। जिम्मेदार प्रतिपक्षी दलों का यह नैतिक दायित्व है कि वे पदस्थ सरकार की रचनात्मक आलोचनाओं के अधिकार का प्रयोग करे। यदि प्रतिपक्षी दल प्रधानमंत्री की उनके कार्यों के लिए आलोचना करते है तब प्रधानमंत्री को स्वयं को बचाने की बजाय उनकी पार्टी को उनका बचाव करने के लिए आगे आना चाहिए।

प्रधानमंत्री को कभी भी किसी तरह के कलंकित करने वाले अभियान में वैयक्तिक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह स्वयं चुनाव अभियान के नाम पर की जा रही इन कीचड़ उछालने वाली करतूतों को बंद करने की पहल करेंगे।■

स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश

राष्ट्रीय उत्थान की क्षमता केवल भाजपा में : राजनाथ सिंह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के 30वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को दिये अपने संदेश में कहा कि आज देश में आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक हर क्षेत्र में भारत के सामने कठिन चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का उत्तर देने की क्षमता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही है। भाजपा की विचारधारा में आर्थिक, और सामाजिक विकास का एक ऐसा मॉडल है जिसमें तकनीकी प्रगति के साथ–साथ गरीब, मजदूर, किसान सभी की समृद्धि सुनिश्चित हो सके, सभी युवकों को रोजगार मिल सके और एक समरसतापूर्ण भेदभाव रहित समाज का विकास हो सके जो राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक गौरव के भाव से परिपूर्ण हो जिसकी प्रेरणा हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्ममानववाद से मिलती है।

श्री सिंह ने कार्यकर्ता से कहा कि भाजपा के इस विचार को हमने मूर्तरूप देकर दिखाया है। भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 6 वर्ष तक चली एनडीए सरकार के दौरान हुआ देश का चहुंमुखी विकास इसको प्रमाणित करता है। हमारी स्थापना के समय ही अटल जी एवं उनके अनन्य साथी आडवाणी जी ने जो दूरदृष्टि दिखाई थी आज देश के समक्ष आन्तरिक सुरक्षा से लेकर आर्थिक विषमता की सभी चुनौतियों का उत्तर उसी दृष्टि से दिया जा सकता है। देश के वास्तविक उत्थान की दृष्टि और क्षमता केवल भाजपा में ही है। हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा की उसी गौरवशाली परम्परा के अनुरूप आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में बनने वाली अगली सरकार भारत को समृद्धि और स्वाभिमान के नये आयामों तक ले जायेगी।

आज भाजपा की विचारधारा और नीतियां राष्ट्र के लिए पहले से अधिक प्रासंगिक और अपरिहार्य हो गयी हैं। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को इन विचारों को जन–जन तक पहुंचाना चाहिए ताकि भाजपा जनता के समर्थन से सशक्त हो सके और भाजपा के नेतृत्व में भविष्य के सशक्त भारत का निर्माण हो सके।

आज भाजपा की विचारधारा और नीतियां राष्ट्र के लिए पहले से अधिक प्रासंगिक और अपरिहार्य हो गयी हैं। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को इन विचारों को जन–जन तक पहुंचाना चाहिए ताकि भाजपा जनता के समर्थन से सशक्त हो सके और भाजपा के नेतृत्व में भविष्य के सशक्त भारत का निर्माण हो सके। ■

कांग्रेस ने डा. अम्बेडकर की उपेक्षा की : लालकृष्ण आडवाणी

14 अप्रैल, 2009 को लोकसभा चुनाव 2009 के लिए दलित चेतना रथ यात्रा को झंडी दिखाते समय श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा सम्बोधित भाषण के प्रमुख बिन्दु

Hkkरतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार डा0 भीमराव अम्बेडकर समता, सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के समर्थक थे। उन्होंने अन्य विद्वानों के साथ मिलकर भारतीय संविधान की रचना की जो विश्व के बेहतरीन संविधानों में से एक है।

25 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा के समापन सत्र में डा0 अम्बेडकर ने एक उत्कृष्ट भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने नए स्वतंत्र राष्ट्र को दो बिन्दुओं पर प्रबोधित किया :

1 मुश्किल से हासिल की गई हमारी आजादी की रक्षा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करके की जानी चाहिए और विगत की मूर्खताओं जिनसे विदेशी आक्रमणकारियों और शासकों को भारत पर शासन करने में मदद मिली थी, को नहीं दोहराया जाना चाहिए।

2 सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है।

भारतीय जनता पार्टी स्वयं इस शिक्षा का पालन करने के प्रति कृत–संकल्प है।

कांग्रेस पार्टी ने डा0 अम्बेडकर को कभी भी अपेक्षित श्रेय नहीं दिया।

इसने सन् 1952 में पहले लोकसभा चुनावों में उन्हें शिकस्त दी।

तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता डा0 एच.वी. हांडे की एक नई पुस्तक (मेकमिलन द्वारा प्रकाशित अम्बेडकर एंड द मेकिंग ऑफ द इंडियन कांस्टीट्यूशन) में प्रकाश डाला गया है कि संविधान सभा में शुरू में भेजे गए 296 सदस्यों में किस तरह डा0 अम्बेडकर को स्थान नहीं मिल सका था। पूर्वी बंगाल के एक दलित नेता ने सदस्य के रूप में अपना नाम वापस लेकर डा0 अम्बेडकर के लिए संविधान सभा में जाने का रास्ता बना दिया।

इसके अलावा, महात्मा गांधी ने ही डा0 अम्बेडकर को मंत्रिमण्डल में शामिल करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को राजी किया था।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि डा0 अम्बेडकर को सन् 1990 में ही ''भारत रत्न'' दिया गया था। यह कार्य वी.पी. सिंह की सरकार द्वारा किया गया, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था।

इसके अलावा, यह मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ही थी जिसने डा0 अम्बेडकर की जन्मभूमि, महू में उनका भव्य स्मारक बनाया। मुझे गतवर्ष इस स्मारक का उद्घाटन करने का सम्मान मिला था। कांग्रेस पार्टी जिसने 50 वर्षों तक इस राज्य पर शासन किया था, ने कभी भी इसकी परवाह नहीं की।

भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण से आगे दृष्टिकोण

भारतीय जनता पार्टी के घोषणा –पत्र में हमने वादा किया है :

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को जारी रखने के अलावा, ''भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज के दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं दूसरे वंचित वर्गों के लिए उद्यमशीलता एवं व्यवसाय के अवसरों को बढ़ाएगी ताकि भारत की सामाजिक विविधता पर्याप्त रूप से इसकी आर्थिक विविधता में प्रतिबिम्बित हो।''

इस प्रकार, हमारे घोषणा–पत्र में डा0 अम्बेडकर के स्वप्न को पूरी तरह से उच्चारित किया गया है।

हमने सीखो और धन कमाओ योजनाओं (learn-and-earn schemes) के जरिए कौशल संवर्धन को बढ़ावा देने हेतु ''अत्यंत पिछड़े समुदायों'' के लिए एक विकास बैंक का भी प्रस्ताव किया है।

डा0 अम्बेडकर के आर्थिक लोकतंत्र के सपने को पूरा करने का यह एक नया दृष्टिकोण है। मैं इसे आरक्षण से

आगे दृष्टिकोण कहूंगा। इसका अभिप्राय है कि हम आरक्षणों की नीति को जारी रखेंगे और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को उद्यमशीलता, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय (प्रोफेशनल्स) और लाभप्रद रोजगार की मुख्य धारा में लाने हेतु महत्वाकांक्षी नई पहलें भी शुरू करेंगे।

उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से अपील

उत्तर प्रदेश में एक पार्टी दलितों के नाम पर चुनकर सत्ता में आई है। दुःख की बात है कि सरकार में इसका कामकाज ऐसा है कि दलितों के कई वर्ग अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इस सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार जो पिछली सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में महामारी की तरह फैले हुए थे, को समाप्त करने का वादा किया था।

दुःख की बात है कि उत्तर प्रदेश में एक भ्रष्ट और अपराधयुक्त सरकार की जगह दूसरी सरकार आ गई है। लेकिन न केवल दलित ही वरन् समाज के सभी वर्ग अपने को छला हुआ महसूस कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की जनता को आगामी लोकसभा चुनावों में सही निर्णय लेने का एक मौका मिला है। मैं उत्तरप्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि वह भारतीय जनता पार्टी तथा इसकी सहयोगी पार्टी–आर.एल.डी. को समर्थन दे और बड़ी संख्या में हमारे उम्मीदवारों को चुनें।

मैं उनसे वादा करता हूं कि यदि नई दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई तो हम उत्तर प्रदेश में स्थिति को व्यवस्थित करेंगे।

मैं भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा को हार्दिक बधाई देता हूं कि उसने अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर कई राज्यों को कवर करते हुए दो दलित चेतना रथ यात्रा शुरू की हैं। मैं 15वीं लोकसभा के चुनावों के लिए पार्टी के अभियान के सन्दर्भ में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिए डा0 सत्यनारायण जटिया, श्री रामनाथ कोविंद, श्री दुष्यंत गौतम और अनुसूचित जाति मोर्चा के अन्य पदाधिकारियों को बधाई देता हूं।

thr:xh Hkktik] thr:xk Hkkjr

■

तमिलनाडू में भाजपा के नेतृत्व में वृहद् गठबंधन की स्थापना

तमिलनाडू में एक 'वृहद् गठबंधन' के निर्माण की घोषणा करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि लोकसभा में उनकी पार्टी को भारी बहुमत प्राप्त होगा और केंद्र में एक 'स्थिर तथा कुशल' सरकार बनेगी।

मंच पर एआईएसएम के अध्यक्ष श्री आर. शरद कुमार, एआईएनएम के नेता श्री कार्तिक (दोनों ही दक्षिण भारत के लोकप्रिय फिल्म अभिनेता रहे हैं, जनता पार्टी अध्यक्ष श्री सुब्रह्ण्यम स्वामी, भारतीय फारवर्ड ब्लॉक के नेता नगई मुगन और डीवी के अध्यक्ष श्री बीटी अरस कुमार (इन सभी पार्टियों ने राज्य में भाजपा के साथ गठबंधन किया है) के साथ मंचासीन श्री वेंकैया नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि कांग्रेस के साथ केवल एक पार्टी डीएमके रह गई है, जिसके पास अनेक कारणों से कोई विकल्प भी नहीं था। जेडी(यू) की तमिलनाडु ईकाई भी भाजपा के साथ शामिल है और दो सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

कांग्रेसनीत सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। देश के सामने बहुआयामी चुनौतियां खड़ी है जिन्हें केवल भाजपा ही हल कर सकती है। आज विश्व के आर्थिक संकट के समय केंद्रीय सरकार का कोई वित्तमंत्री नहीं है।

श्री नायडू ने आरोप लगाया कि कांग्रेसनीत सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। देश के सामने बहुआयामी चुनौतियां खड़ी है जिन्हें केवल भाजपा ही हल कर सकती है। आज विश्व के आर्थिक संकट के समय केंद्रीय सरकार का कोई वित्तमंत्री नहीं है। इसी से आज की सरकार की अपार असफलता दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री लालकृष्ण आडवाणी पर आरोप लगाना निरर्थक है क्योंकि वे एकदम साफ, सक्षम और चरित्रवान व्यक्ति हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मनमोहन से लगभग चुनाव प्रचार नहीं करवाया है, इसी से पता चलता है कि पार्टी के मन में श्री मनमोहन सिंह के लिए कोई जगह ही नहीं है। यह प्रधानमंत्री पद का अपमान है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री एल.गणेशन ने पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी की और कहा कि एआईएसएम पांच सीटों–टयूटीकोरिन, त्रिरूनेलवेल्ली, तेनकाशी, नमक्कत और तिरूपुर पर चुनाव लड़ेगी। एआईएनएम दो सीटों–विरूदनगर और थेनी तथा जनता दल (यू) दो सीटों–अरकोनम और तिरूवल्लूर पर चुनाव लड़ेगी।

सत्ता में आए तो काला धन वापस लायेंगे : आडवाणी

श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा मुम्बई, 17 अप्रैल 2009 को संवाददाता सम्मेलन में जारी वक्तव्य

ने 29 मार्च, 2009 को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए स्विटजरलैंड के गुप्त बैंक खातों तथा विश्व के अन्य टैक्स हेवन्स में बड़ी मात्रा में अवैध धन का महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया था। यह संवाददाता सम्मेलन, 2 अप्रैल, 2009 को लंदन में जी–20 शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में किया गया था जिसमें इस तरह से जमा अवैध धन का मुद्दा चर्चा हेतु उठाया जाना था। प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह, जिन्होंने जी–20 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, से राष्ट्र को यह उम्मीद थी कि वे इस वैश्विक मंच पर भारत की चिन्ताओं और अपेक्षाओं को जोरदार ढंग से उठायेंगे। दुःख की बात है कि उन्होंने इस मुद्दे पर केवल औपचारिकता ही निभाई। इसके विपरीत ऑरगेनाईजेशन ऑफ इक्नॉमिक कोऑपरेशन एण्ड डेवलेपमेंट (ओईसीडी), जोकि समृद्ध राष्ट्रों का एक समूह है, स्विटजरलैंड जैसे देशों में बैंकिंग गोपनीयता को समाप्त करने की मांग करते हुए काफी होहल्ला मचा रहे थे।

- *स्विस बैंक खातों और अन्य टैक्स हेवन्स में जमा भारतीय धन को वापस लाने हेतु प्रभावी कार्रवाई करना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की भावी सरकार का 100 दिनों का शीर्ष कार्यक्रम होगा।*
- *कांग्रेस को सबक सिखायें जिसमें भ्रष्टाचार और आपराधिक कृत्यों से जमा की गई धनराशि को वापस भारत लाने की कोई इच्छा–शक्ति नहीं है।*

मैंने नई दिल्ली में हुए अपने प्रेस संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि केन्द्र की भावी भाजपानीत सरकार यदि सत्ता में आई, विदेशी बैंकों में अवैध रूप से जमा भारतीय धन को वापस लायेगी और उसे विभिन्न महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं में इस्तेमाल करेगी। मैंने एक टास्क फोर्स का गठन करने की भी घोषणा की थी जो ऐसे विशिष्ट कदमों की सिफारिश करेगा जिनपर भावी सरकार अपने वादे को वास्तविकता में बदलने हेतु अमल करेगी।

मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा हूं कि टास्क फोर्स ने संलग्न अंतरिम रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। मैं टास्क फोर्स के सदस्यों – श्री एस. गुरूमूर्ति (चार्टर्ड एकान्टेंट तथा लेखक, चैन्नई); श्री अजीत डोभाल (सुरक्षा विशेषज्ञ, नई दिल्ली); और डॉ आर वैद्यनाथन (प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस, भारतीय प्रबंध संस्थान, बैंगलौर); और श्री महेश जेठमलानी (वरिष्ठ अधिवक्ता, मुम्बई) को हार्दिक अन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह उत्कृष्ट कार्य किया है।

टास्क फोर्स की रिपोर्ट चार महत्वपूर्ण कारणों से उपयोगी है। पहला, इसमें बड़े वैश्विक खतरे के सन्दर्भ में विदेशों के गुप्त बैंक खातों में जमा अवैध भारतीय धन की समस्याओं को दर्शाया गया है जिससे पश्चिमी देशों ने अपनी आंतरिक बाध्यताओं के कारण इस समस्या से लड़ने हेतु संकल्प लिया है। इसलिए, टास्क फोर्स ने ठीक ही उल्लेख किया है कि भारत को बैंकिंग गोपनीयता तथा टैक्स हेवन्स के विरूद्ध वैश्विक लड़ाई में एक सक्रिय सहयोगी के रूप में हिस्सा लेना चाहिए।

दूसरे, टास्क फोर्स ने सही कहा है कि 'लूट के तथ्यों' पर कोई सवाल नहीं उठा सकता यद्यपि 'लूट के तरीकों' पर बहस हो सकती है। विदेशों में किए गए अध्ययन के आधार पर टास्क फोर्स ने कहा है कि स्विस बैंक खातों ओर अन्य टैक्स हेवन्स में 500 बिलियन अमेरिकी डालर (25 लाख करोड़ रूपए) से 1. 4 ट्रिलियन अमेरिकी डालर (70 लाख करोड़ रूपए) तक भारतीय धन है। इन आंकड़ों की पुष्टि इस महीने में लंदन में हुए जी–20 शिखर सम्मेलन में ओईसीडी (ऑरगेनाईजेशन ऑफ इक्नॉमिक कोऑपरेशन एण्ड डेवलेपमेंट) की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट जिसमें विभिन्न टैक्स हेवन्स में दुनिया की सम्पत्ति के बारे में बताते हुए कहा गया है कि 11.5 ट्रिलियन अमेरिकी डालर (575 लाख करोड़ रूपए) जमा हैं।

तीसरे, टास्क फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की लचर नीति को मुखरित किया है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भाजपा के इन प्रयासों की खिल्ली तक उडाई है। मेरी मतदाताओं से अपील है कि : कांग्रेस को सबक सिखाओ क्योंकि उसके पास भ्रष्टाचार और अपराधिक कृत्यों से जमा धन को वापस लाने की कोई राजनीतिक

इच्छा–शक्ति नहीं है। 'भ्रष्टाचार' शब्द का कांग्रेस के घोषणा–पत्र में उल्लेख तक नहीं है।

चौथे, टास्क फोर्स ने विदेशों में स्थित टैक्स हेवन्स से भारतीय काले धन को वापस लाने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय रणनीति के रूप में कुछ विशेष कदम सुझाये हैं :

टास्क फोर्स द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें :

वैश्विक रणनीति:

igyk dne % बैंकिंग गोपनीयता को उजागर करने के संबंध में भारत की आवश्यकताओं के संदर्भ में वैश्विक सामाधान के लिए भारत में एक शक्तिशाली जनमत बनाना पूर्व शर्त है। दुनिया इस वैश्विक मुद्दे पर सशक्त घरेलू जनमत का आदर करती है। भारत को सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि गुप्त बैंकों और टैक्स हेवन्स के खिलाफ वैश्विक अभियान के साथ जुड़ने का यह अच्छा समय है।

इस मुद्दे पर राष्ट्रीय आम सहमति की अनुपस्थिति में प्रतिबद्ध टीम वाला सिर्फ एक मजबूत नेता ही दृढ़ राष्ट्रीय इच्छा–शक्ति जागृत कर सकता है जो इस गंभीर विषय से निपटने के लिए जरूरी है। जो इस कदम का विरोध करें उन्हें काले धन का समर्थक माना जाना चाहिए।

nwljk dne % भारत जी–20 राष्ट्रों द्वारा गुप्त बैंकों के विरुद्ध चल रहे प्रयासों का मूक दर्शक भर न रहे। इसमें वह सक्रिय सदस्य बने और इस सोच को बदले कि वो गुप्त बैंकों और टैक्स हेवन्स के खिलाफ नहीं है।

rhljk dne % भारत को एलजीटी बैंक के गुप्त खातों से भारतीय नामों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए जर्मन सरकार से आग्रह करना चाहिए। यदि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का जनादेश मिलता है तो इसे जर्मनी में एक विशेष दूत भेजना चाहिए जो एलजीटी बैंक खातों में दर्ज भारतीय लोगों के नामों का ब्यौरा ला सके जिसे जर्मनी देने को तैयार है।

pkFkk dne % भारत को वैश्विक और बहुपक्षीय तौर पर प्रयास करने चाहिए जोकि बैंकिग गोपनीयता को हटाने का एकमात्र समाधान है।

ikpok dne % बैंकिंग गोपनीयता को समाप्त करने के लिए पश्चिम की जरूरतों से अलग भारत की विशेष आवश्यकता भी हैं।

भारत को पश्चिम के साथ मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर सहमति प्राप्त ओ.ई.सी.डी. कर मानकों के बहुपक्षीय प्रयासों में हिस्सा लेना चाहिए। वैश्विक स्तर पर चल रही ठोस कार्रवाई को इस तथ्य से देखा जा रहा है कि जी–20 देशों द्वारा टैक्स हेवन्स और गोपनीय बैंकिंग व्यवस्था को काली सूची में डालने की धमकी के अपेक्षित परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं।

जब भारत सूचना के आदान–प्रदान की व्यवस्था के जरिये बैंक की गोपनीयता से पर्दा उठाने में कामयाब हो जायेगा तो वह न सिर्फ आज के नाम और धनराशि का पता लगा सकता है बल्कि उसे बैंक खाताधारकों के सम्पूर्ण आर्थिक इतिहास की जानकारी भी मिल जायेगी।

NBk dne % हम सिफारिश करते हैं कि भारत एक विशेष दूत नियुक्त करे जिसे कर टैक्स हेवन्स और गुप्त बैंकों के मुद्दे की पर्याप्त जानकारी हो और जो गुप्त बैंकों तथा कर टैक्स हेवन्स का पर्दाफाश करने हेतु तथा विशेष रूप से भारत समर्थक कानून बनाने का काम कर सके।

राष्ट्रीय रणनीति

1. स्विटजरलैंड तथा अन्य टैक्स हेवन्स की यात्रा करने वाले लोगों के बारे में यात्रा संबंधी सूचना का एकत्रीकरण। यह प्रक्रिया कैबिनेट मंत्रियों तथा अन्य उच्च राजनीतिक व्यक्तियों से शुरू की जानी चाहिए।
2. टैक्स हेवन्स की निगरानी जिनका भारत के साथ बार–बार काफी अधिक लेन–देन होता है।
3. भारत 'वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स' का पूर्णकालिक सदस्य बने।
4. सुरक्षा प्रयोजनों के लिए वित्तीय खुफिया सूचनाओं का उपयोग। अवैध धन राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का सम्भावित स्रोत है। इसलिए हम सिफारिश करते हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस बारे में खुफिया सूचना जुटाने के लिए विशेष रूप से काम दिया जाना चाहिए।
5. **विधायी सहायता :** जिस प्रकार ओबामा प्रशासन टैक्स हैवेन विरोधी कानूनों की योजना बना रहा है, ठीक उसी तर्ज पर भारत को भी टैक्स हैवन्स और भारत में संचालित स्विटजरलैंड जैसे गुप्त स्थानों को निशाना बनाना चाहिए। हम सिफारिश करते हैं कि सख्त कानून बनाने चाहिए जिनमें यदि किसी पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो आरोपी को अपनी बेगुनाही खुद करनी होगी।
6. **उच्चस्तरीय कार्यदल :** हम सिफारिश करते हैं कि सूचना एकत्र करने, उसकी छानबीन करने और जहां संभव हो वहां कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए भारत सरकार को उच्चस्तरीय कार्यदल का गठन करना चाहिए, जिसमें वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों, विधि मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, आर्थिक खुफिया सूचना इकाइयों, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई, के प्रतिनिधि और अन्य विशेषज्ञ शामिल हों। अगर जरूरी हो तो रक्षा मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय आदि जैसे कुछ बड़े मंत्रालयों में खरीदारी में व्यापक स्तर पर दलाली के आरोप लगते हैं, ऐसे में इनके प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा सकता है।
7. अवैध धन के मालिकों का इतिहास भी उजागर किया जाना चाहिए : हम सिफारिश करते हैं कि जब भारत सूचना के आदान–प्रदान की व्यवस्था के जरिये बैंक की गोपनीयता से पर्दा उठाने में कामयाब हो जायेगा तो वह न सिर्फ आज के नाम और धनराशि का पता लगा सकता है बल्कि उसे बैंक खाताधारकों के सम्पूर्ण आर्थिक इतिहास की जानकारी भी मिल जायेगी। ■

आम आदमी पूछता है
प्रधानमंत्रीजी, बता तो दीजिए, आप मुझसे क्यों भय खाते हैं?

ç'kkr xk;y

मैं साधारण सा भारतीय– आम आदमी हूं जिसे आप भूल गए हैं।

परन्तु मैं आपको नहीं भूला हूं। मुझे आपके 5 वर्षों की खूब याद है, जिससे मेरे मन में भारी आक्रोश है।

बताइए, मैं आपको प्रधानमंत्री क्यों बनाऊं?

- आप तो यह चुनाव भी नहीं लड़ रहे क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कभी भी लोगों के सामने आने का साहस जुटा ही नहीं सकते।
- आप तो लोगों का जनादेश प्राप्त करने की बजाए मात्र प्रधानमंत्री के रूप में नामजद होना ही पसंद करते हैं।
- क्या आप मुझसे अपने 5 वर्षों के शासन के रिकार्ड को भुला देना चाहते हैं?
- आप ने तो भारत की बजाए विदेशों में घूमने में अधिक समय बिताया। भला बताइए, आपकी अनुपस्थिति में कौन राज–काज चलाता था?
- आप अपने को बड़ा भारी अर्थशास्त्री मानते हैं, परन्तु आपने तो देश की अर्थव्यवस्था ही डुबो कर रख दी।
- आप गरीब आदमी का वोट चाहते हैं, परन्तु आपने तो बहुत भारी संख्या में करोड़पति लोगों को उम्मीदवार बनाकर खड़ा कर दिया है।
- होना तो यह चाहिए था कि आप देश के निर्माण का कार्य करते, परन्तु आपने तो देश की राजमार्ग परियोजनाओं तक को बंद करके रख दिया।
- आपको तो देश का रक्षक बनना चाहिए था परन्तु आज हम यही देखते हैं कि कोई भी हत्यारा हमारे घरों, बाजारों, होटलों और कहीं भी आकर हमारी हत्या कर देता है।
- आपने तो उन आतंकवादियों तक पर कार्रवाई नहीं की जो आए दिन नागरिकों और सैनिकों की हत्या करके चले जाते हैं। आपकी तो बस इतनी मंशा रह गई है कि हम अपनी इन हत्याओं के आदी बन जाएं।
- यह आपकी कमजोरी का ही नतीजा है कि नक्सलवादियों की संख्या निरंतर तेजी से बढ़ती चली जा रही है। वे जब चाहें मतदाताओं और सुरक्षाबलों पर हमला कर देते हैं परन्तु भला आपको इसकी परवाह ही कहां है?
- आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया क्योंकि ये लोग असम और दिल्ली में अब आपके भारी वोट बैंक बन गए हैं।
- आपने कभी भी किसी भारतीय को न्याय नहीं दिलाया क्योंकि आप तो केवल एक ही समुदाय का पक्ष लेने में जुटे रहे हैं।
- आपने 1984 के सिखों के नरसंहार के लिए उनसे माफी मांगी परन्तु आपने देश से माफी मांगने में शर्म महसूस की। आपने भारतीयों से माफी नहीं मांगी।
- आपने ऐसे मंत्रियों को नियुक्त किया जिनमें से बहुत से लोगों का आपराधिक इतिहास था और वे अदालतों में अपने घिनौने आरोपों के लिए लांछित थे। आपने दंगे और बम विस्फोटों के पीड़ितों को न्याय के मामले में विलम्ब किया।
- आपने बड़े लम्बे चौडे वादे किये और फिर पूरा न कर पाने पर खेद प्रगट करते रहे। परन्तु इसके अलावा और तो कुछ आपने किया नहीं।
- आपने कभी भी हमसे दिल से बात तक नहीं की क्योंकि आप तो बस सदा ही लिखे भाषण पढ़ने में ही मशगूल रहे।
- आपको तो सार्वजनिक बहस से भी डर लगता है।
- आपके कैबिनेट मंत्री खुद अपनी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इसी को 'ग्रांड एलाइंस' अर्थात् भव्य गठबंधन का नाम दिया जा सकता है।
- आपने परमाणु सौदे पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर करने से पहले हमें उसकी शर्तें तक बताने में कोताही बरती। आज भी हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है।
- जब बिहार और गोवा के राज्यपालों ने लोकतंत्र की सारी मर्यादाएं तोड़ डाली तब भी आपने लोकतंत्र बचाने के लिए कुछ नहीं किया।
- आपको तो हजारों सैनिकों द्वारा अपने मैडल लौटाने पर भी कोई चिंता तक व्याप्त नहीं हुई।
- किसानों के लिए बहुत कुछ किये जाने के बड़े लम्बे चौड़े दांवों की बात कहने पर भी किसान आत्महत्याएं करते रहे, फिर भी उनके बारे में आपको जरा सी सुध तक नहीं आई।
- आपने हर कदम पर 'परिवार' की रक्षा करते हुए लोकतंत्र की जानबूझ कर बलि दे डाली।
- आपके अपने ही कैबिनेट मंत्रियों ने आपकी घोर उपेक्षा की। आप न तो किसी को नियुक्त कर सकते थे और न ही किसी को बर्खास्त कर सकते थे। ऐसे हर मंत्री ने सदा ही आपकी 'सुपीरियर पावर' के 10 जनपथ पर ही जाकर दरवाजा खटखटाया।
- आपने अपनी 'सुप्रीम नेता' के हाथ में सभी शक्तियां सौंप कर प्रधानमंत्री के सम्मान और अधिकार को गहरा आघात पहुंचाया।

और फिर भी आज आप उसी पद पर विराजमान होने की चाहत रखते हैं?

क्यों? क्या किसी ने फिर आपको कहा है कि आपको फिर से प्रधानमंत्री बनना है?

भले ही आप निष्ठा की छवि के पीछे अपना मुंह छुपा रहे हों, परन्तु मैं तो आपका असली चेहरा देख ही रहा हूं। मैं आम आदमी हूं और मुझे किसी से भय नहीं लगता है।

iètkkue=h] vki D;k Mj jg g\ vkidk fdll Mj yx jgk g\ e>l\ gk] yxuk Hkh pkfg,A ■

हम जनता को एक समृद्ध राष्ट्र देना चाहते हैं : आडवाणी

राजग की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार श्री लालकृष्ण आडवाणी का मानना है कि अयोध्या में राममंदिर जरूर बनेगा और देश में एक दिन 'समान नागरिक संहिता' लागू होगी। श्री आडवाणी के साथ राष्ट्रीय सहारा के श्री रोशन ने दिल्ली, बेलगाम, अहमदाबाद, चित्रदुर्ग और हुबली की यात्रा की। प्रस्तुत है इस दौरान उनसे हुई विस्तृत बातचीत के प्रमुख अंशः—

- इस बार आप प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आप जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं?

मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हम दूसरे दलों से आगे हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि बहुत आगे हैं। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं। हम हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश में अच्छा कर रहे हैं। अन्य राज्यों से भी हमें अच्छी रिपोर्ट मिल रही है।

- यदि सरकार बनाने में कुछ सीटों की कमी पड़ गयी तो क्या थर्डफ्रंट एवं अन्य गैर कांग्रेसी दलों से समर्थन मांगेंगे?

थर्ड फ्रंट है कहां? जो दल कांग्रेस का विरोध करते हैं वे आखिर जाएंगे कहां, हमारे ही पास आएंगे। मेरा मानना है कि थर्ड फ्रंट को भाजपा और कांग्रेस दोनों में से किसी का समर्थन नहीं मिलेगा।

- भाजपा के घोषणा पत्र में फिर से राममंदिर का निर्माण, धारा ३७० हटाने और समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई। पिछली बार जब भाजपा सत्ता में थी तो इन तीनों ही मुद्दों पर कोई काम नहीं हुआ। क्या इस बार भी सिर्फ दिखावे के लिए इन्हें चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर दिया गया है?

यह बहुत बड़ा विषय है। यह मुद्दा गठबंधन और विचारधारा की राजनीति की मजबूरी है। हमने अपने समर्थकों को समझाने के लिए यह मुद्दा शामिल किया है, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि हम इसे चुनाव का मुद्दा नहीं बनाना चाहते। मैं आने समर्थकों और आरएसएस को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इन मुद्दों को पूरा करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाये। क्योंकि हमारे सहयोगियों ने साफ कह दिया था कि हम परमाणु संधि पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के तीनों मुद्दों पर अमल नहीं कर सकते। हम फिर अपने समर्थकों को समझा रहे हैं कि फिर से अपने सहयोगियों से बात करेंगे। मुझे यह उम्मीद है कि समान नागरिक संहिता भी देश में जरूर लागू होगी।

- तो क्या कभी राममंदिर नहीं बन पायेगा?

जरूर बनेगा। मुझे पूरी आशा है कि हिन्दू और मुसलमान एक साथ बैठकर मंदिर का निर्माण कराएंगे। यदि मुसलमान स्वयं आगे आते हैं और मंदिर का निर्माण करते हैं तो देश के हिन्दुओं में मुसलमानों के प्रति धारणा बदलेगी।

- जनसंघ से लेकर भाजपा के आज तक के सफर में मुसलमान भाजपा का अछूत मानता है, उनकी नाराजगी दूर कैसे करेंगे?

देश का मुसलमान वोट बैंक की राजनीति का शिकार हुआ है। कांग्रेस ने देश विभाजन के चिह्नों को जिंदा रखा है। जिसके कारण मुसलमान राष्ट्र की मुख्य धारा में आज भी घुलमिल नहीं पाते। सच्चर समिति की रिपोर्ट से साफ है कि पिछले 60 साल देश में राज करने पर भी कांग्रेस ने मुसलमानों का सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं किया। आज भी वे पिछड़े हैं। हमारे आलोचकों ने हमसे दूर रखने के लिए उन्हें डराये रखा। कांग्रेस ने पहले 30 साल हमारी आलोचना इस आधार पर की कि हमने (आरएसएस) ने गांधी जी की हत्या की और अब आगे 30 साल तक यही आलोचना करते रहेंगे कि हमने बाबरी मस्जिद गिराई। मैं नहीं चाहता कि मंदिर मुद्दा बने। इसलिए हमने अपने नारे 'जस्टिस फार ऑल' के साथ 'डिस्क्रिमिनेशन फॉर नन यानि किसी के साथ भेदभाव नहीं' बनाया है।

- देश में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। यदि आपकी सरकार केन्द्र में आई तो क्या करेंगे?

मैं मानता हूं कि जितनी मंदी पश्चिम के देशों में है उतनी भारत में नहीं है। वर्तमान सरकार ही मंदी से निपट सकती थी, लेकिन तीन महीने सरकार चलाने का लालच उसे डुबा गया। हम 1999 में विश्वास मत हारने के चुनाव में चले गये थे।

- आपने अपने घोषणा पत्र में दो रुपये किलो गेहूं/चावल देने, लाड़ली लक्ष्मी योजना शुरू करने, कर्ज रहित किसान की बात की है। आखिर इतना पैसा कहां से आएगा?

गरीबों को भोजन देना उन पर अहसान करना नहीं है। यह हमारा कर्त्तव्य है। विदेशों में गरीबों को सब्सिडी मिलती है। हम उन्हें सब्सिडी नहीं दे सकते तो भोजन देना हमारा कर्त्तव्य है। लड़कियों का ड्रापआउट रेट रोकने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना चलाने में कोई हर्ज नहीं है। जब हमने स्वर्णिम चतुर्भुज और ईस्ट, वेस्ट, नार्थ तथा साउथ कॉरीडोर बनाने का काम शुरू किया था तब भी कहा गया था कि कैसे बनेगा, लेकिन जब काम शुरू करो तो हो ही जाता है। देश में असीमित संभावनाएं हैं। परंपरा से हटकर भी कदम उठा सकते हैं। जैसे मैंने स्विस बैंक में रखे काले धन को भारत लाने की मांग कर बहस छेड़ी है।

- इस बार के चुनाव में आपके प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

मैं मानता हूं कि महंगाई और रोजगार छिनना इस बार के मुद्दे हैं। किसानों का आत्महत्या करना शर्म की बात है। मुंबई घटना के बाद देश की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न लग गए हैं। आईपीएल का आयोजन भी बाहर हो रहा है। हम जनता को एक समृद्ध राष्ट्र देना चाहते हैं। हम सुरक्षित देश, भयमुक्त समाज, भूखमुक्त देश, कर्जमुक्त और समृद्ध किसान देखना चाहते हैं। हम पानी को मौलिक अधिकार, एफोर्डेबल स्वास्थ्य और सबको शिक्षा देना खहते हैं।■

भव्य भारत बनाने का दृढ़ संकल्प लें

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की देशवासियों से अपील

yk लोकसभा के चुनावों का बिगुल बज गया है। प्रायः प्रत्येक पांच वर्ष बाद होने वाले लोकतंत्र के इस महोत्सव की चहल–पहल देखी जा सकती है। पहली लोकसभा से 14वीं लोकसभा के चुनावों तक एक कार्यकर्ता, प्रत्याशी और पार्टी के प्रचारक के रूप में आपके बीच रहने का सौभाग्य मुझे मिला। परन्तु इस बार अस्वस्थता के चलते चाहकर भी आपके बीच नहीं आ पा रहा हूं। मगर देश की नियति की दृष्टि से महत्वपूर्ण इन चुनावों में आपकी चिंता और चिंतन में मैं भी शामिल हूं।

हम सबका चिंतित होना स्वाभाविक है कि आगामी लोकसभा का स्वरूप क्या होगा? कौन सा दल या दलों का गठबन्धन सरकार बनाएगा? कौन प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करेगा? मित्रों, आज फिर से देश तकदीर के तिराहे पर खड़ा है। एक रास्ता यूपीए सरकार की तरफ जाता है जिसने पांच वर्षों में विकास और सुरक्षा की अपराधिक उपेक्षा की है। दूसरा रास्ता उन दलों की ओर जाता है जिनका अधिकतम कार्यक्रम जोड़–तोड़ कर सत्ता में घुसना है। और तीसरा रास्ता भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए की ओर जाता है जो देश में राजनीतिक स्थिरता, विकास, सुशासन और सुरक्षा के संकल्प से बंधा है। अपने 6 वर्ष के शासन में उसने इस संकल्प को साकार करके दिखाया है और आने वाले समय में भी इस संकल्प को यथार्थ में बदलने को कटिबद्ध है। आपका फैसला देश का भविष्य तय करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आप सोच–समझकर सही निर्णय करेंगे।

मित्रों, ग्यारह वर्ष पूर्व बारहवीं लोकसभा के चुनावों के बाद हमने अनेक क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन (एनडीए) बनाया। छः वर्ष तक गठबन्धन की सरकार चली। इससे जहां अस्थिर राजनीति में स्थिरता आई, वहीं विकास तेज गति से हुआ। हमारा गठबन्धन परस्पर विश्वास और सम्मान पर आधारित रहा है। गठबन्धन मजबूरी से नहीं, मन से किए जाते हैं। यही हमारे और दूसरे गठबन्धनों में फर्क है।

आइए, श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में आगामी सरकार बनाने व भव्य भारत का निर्माण करने का दृढ़ संकल्प लें।

- हमारी राजग सरकार ने सर्वप्रथम परमाणु बम का सफल परीक्षण कर भारत को दुनिया के परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा किया।
- आतंकवाद से सख्ती से निपटने हेतु कड़ा कानून और नीतियां अपनाई।
- महंगाई पर पूरी तरह नियंत्रण रखा। किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरु कर सड़कों का जाल फैलाया।
- गांवों में पक्की बारहमासी सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की।
- मोबाइल क्रांति के जरिए दिलों की दूरियां कम कीं।
- हमने देश भर की नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना शुरु की ताकि सूखे की विभीषिका से देश को मुक्ति मिल सके।
- विकास का लाभ शहरों सहित गांव–गांव तक पहुंचाया। गरीब, किसान व मध्यमवर्ग तक लाभ पहुंचाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी।
- हमने पड़ोसियों के साथ मधुर सम्बन्ध बनाने की कोशिश की लेकिन भारत की सुरक्षा और सम्मान की कीमत पर नहीं।

ऐसे और अनेक कामों को गिनाया जा सकता है जिनसे आप परिचित हैं।

मैं आप सभी का अत्यंत आभारी हूं कि पिछले दिनों अस्वस्थता के दौरान भी आपने मुझे इतना अपनापन और स्नेह दिया। मगर मुझे अपने स्वास्थ्य से ज्यादा चिंता अपने भारत के स्वास्थ्य की है। इसका उपचार आपके दृढ़संकल्प से ही हो सकता है। एक ऐसा संकल्प जो चुन सके 'मजबूत नेता और निर्णायक सरकार' – जिसका वायदा भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जिसे श्री आडवाणीजी पूरा भी करेंगे।

मित्रों, इतने वर्षों से मेरा और मेरे दल तथा सहयोगियों का एक ही सपना रहा कि कैसे भारत को हम सशक्त, समृद्ध और बलशाली बना सकें। मेरी

इस यात्रा में अनेक सहयोगी रहे। परन्तु उन सब में सबसे अधिक निकट और प्रतिभाशाली सहयोगी रहे श्री लालकृष्ण आडवाणी। सन् 1952 से हम दोनों साथ–साथ काम करते आ रहे हैं। विपक्ष में और सरकार में हमने मिलकर काम किया है। उनकी बुद्धिमता, वैचारिक स्पष्टता और सबको साथ लेकर चलने और साधने के कौशल का मैं कायल हूं। भारतीय राजनीति में उनका अप्रतिम योगदान है। भाजपा आज जिन बुलन्दियों पर पहुंची है, उसमें उनकी बड़ी भूमिका है। उनका निष्कलंक चरित्र और दृढ़–संकल्पी व्यक्तित्व भारतीय राजनीति में एक दीप स्तम्भ की भांति है। वह चुनौतियों को स्वीकार कर उन्हें परास्त करने में दक्ष हैं। वे एक चिंतनशील राजनेता हैं। आतंकवाद के विरूद्ध हमारी लड़ाई में वे एक दृढ़–संकल्पी योद्धा हैं। मेरा मानना है कि आज भारत को उन जैसे राजनेता की ही जरूरत है।

उनकी आत्मकथा की प्रस्तावना में मैंने लिखा है : ''यह पुस्तक वस्तुतः एक संवेदनशील मनुष्य और विशिष्ट नायक की उल्लेखनीय जीवन यात्रा का वृतांत है, जिनकी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अभी सामने आना शेष है।'' मेरा मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां सामने आयेंगीं। अतः यह चुनाव एक सुअवसर है।

मैं आप सभी से, विशेषकर अपने नौजवान साथियों से एक अच्छे और सुखद परिवर्तन के लिए अपील करता हूं कि आप अपना समर्थन, सहयोग और वोट भारतीय जनता पार्टी व सहयोगी दलों को दें जिससे आडवाणीजी उस स्वप्न को पूरा कर सकें जो हमने साथ–साथ देखा है। वे देश के शासन को एक नई दिशा दे सकें तथा उन अधूरे कामों को आगे बढ़ा सकें जिनकी विगत वर्षों में उपेक्षा हुई है। गरीबी, भुखमरी, बेकारी, लाचारी, अन्याय से मुक्त भारत बना सकें। आप तक यह संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह और उनके वरिष्ठ सहयोगियों के नेतृत्व में लाखों कार्यकर्ता जुटे हैं।

आइए, श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में आगामी सरकार बनाने व भव्य भारत का निर्माण करने का दृढ़ संकल्प लें।

धन्यवाद। ■

प्रधानमंत्री लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं : अरुण जेटली

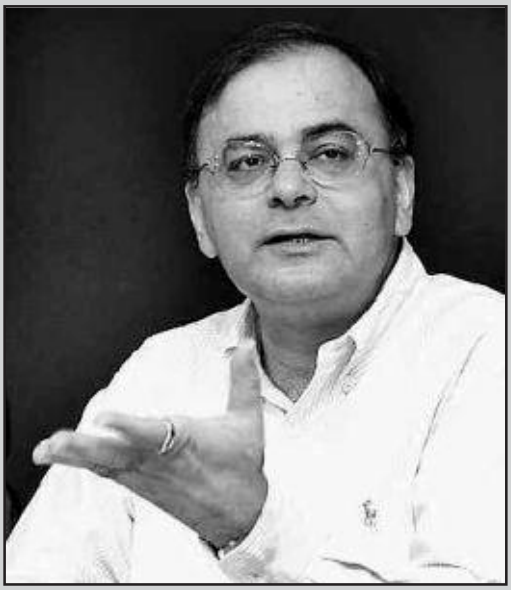

गत 12 अप्रैल को चण्डीगढ़ में कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण जेटली ने कहा कि श्री मनमोहन सिंह सबसे कमजोर प्रधानमंत्री रहे हैं जिहें यह तक भी मालूम नहीं है कि कांग्रेस नेता श्री जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दी गई है।

श्री जेटली ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं?

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने श्री जगदीश टाइटलर और श्री सज्जन कुमार को टिकट देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी का बर्ताव किया है और वह दोगली बातें कर रही है जबकि उसे मालूम था कि नानावटी जांच आयोग ने 1984 के दंगों में हिंसा फैलाने और भड़काने के आरोप में उन्हें दोषी माना था।

उन्होंने कहा कि यह देश के लिए शर्म की बात है कि 1984 की आहकारी घटना में किसी को दण्ड नहीं मिला जिसमें 3000 अधिक लोगों की जानें चली गई थी।

उन्होंने कांग्रेसनीत यूपीए सरकार पर भी आरोप लगाया कि उसी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ गई है।

उन्होंने कहा कि आज जब विदेशी भारत के बाजारों से अपना निवेश हटा रहे हैं तब सरकार ने ब्याज दरें बढ़ाकर और मुद्रा आपूर्ति घटाकर मूर्खतापूर्ण कार्य किया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो गई है।

श्री जेटली का यह भी आरोप था कि यूपीए सरकार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बनाए नहीं रख सकी क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन में निरंतर मतभेद बना रहा। कमजोर सरकार होने कारण आर्थिक और सुरक्षा मोर्चों पर राष्ट्रीय चुनौतियां जटिल बनती चली गई हैं।

हाल में ही भाजपा के लिए यह उत्साहवर्धक बात रही है कि चार कांग्रेसी नेता अपने समर्थकों के साथ श्री जेटली की उपस्थिति में शामिल हो गए हैं।

ये नेता है श्री सुशील कुमार बंसी, अरविन्द पाण्डे, श्रीपाल वर्मा और उमेश गुप्ता।■

श्री लालकृष्ण आडवाणी ने जारी किया आधारभूत ढांचा दृष्टिकोण–पत्र

'हर हाथ को काम, हर खेत को पानी'

गत 21 अप्रैल, 2009 को वरिष्ठ भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने बंगलुरू में पार्टी के आधारभूत ढांचा दृष्टिकोण (इन्फ्रास्ट्रक्चर विजन) को जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने प्रेस वक्तव्य में कहा कि 15वीं लोकसभा के चुनावों के लिए पार्टी के घोषणा–पत्र में इसके बारे में जो उल्लेख किया गया था, उसकी अपेक्षा इस दस्तावेज में हमारी व्यापक सोच और योजनाओं तथा एक सशक्त, समृद्ध और आत्मविश्वासी भारत के लिए रखी जाने वाली नींव का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

श्री आडवाणी ने कहा कि पार्टी का यह मानना है कि भारत में 80 प्रतिशत आधारभूत ढांचा विकास के लिए अभी भी सार्वजनिक निवेश की जरूरत है। इस उत्तरदायित्व को समझते हुए भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन की भावी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में परियोजना सुपुर्दगी की कार्यकुशलता को तेज करने और निजी क्षेत्र में परियोजना के कार्यान्वयन को कारगर बनाने के लिए साहसिक कदम उठाएगी।

भारतीय जनता पार्टी के आधारभूत ढांचा दृष्टिकोण की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता है – विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्रीय महत्व की 100 परियोजनाओं को अपनाने और उन्हें समयबद्ध ढंग से कार्यान्वित करने की प्रतिबद्धता। इन परियोजनाओं में ये शामिल हैं :

जल : दृष्टिकोण – 'हर हाथ को काम, हर खेत को पानी' और प्रत्येक घर के लिए स्वच्छ पेयजल। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए (1) नदी जोड़ो परियोजना का तेजी से कार्यान्वयन करना (2) बड़ी सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं को पूरा करना (3) देश के 6 लाख गांवों में से प्रत्येक गांव में कम से कम एक नई जल संरक्षण सुविधा (तालाब, रोकबांध आदि) का निर्माण करना तथा भारतीय शहरी इलाकों में वर्षा जल के एकत्रीकरण को सार्वभौमिक बनाना (4) 'पानी की एक–एक बूंद से अधिक फसल उगाने' के लक्ष्य को बढ़ावा देने हेतु लघु सिंचाई पद्धतियों का व्यापक विस्तार करना।

ऊर्जा और बिजली : दृष्टिकोण – प्रत्येक घर, प्रत्येक खेत और प्रत्येक फैक्ट्री के लिए 24 घंटे सातों दिन सस्ती दरों पर बिजली। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए (1) पांच वर्षों में 1,20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी करना (यूपीए सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में 30,000 मेगावाट से भी कम अतिरिक्त बिजली पैदा की) (2) इसमें से हवा, सौर ऊर्जा और बायोमास पर आधारित परियोजनाओं जैसे गैर–परम्परागत संसाधनों से 20: का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखना। ऊर्जा संरक्षण तथा हरित प्रौद्योगिकियों के अभिग्रहण हेतु राष्ट्रीय मिशन में काम करने के लिए विश्वभर से सर्वोत्तम बुद्धिजीवियों को आमंत्रित करना ताकि भारत को ग्रीन एनर्जी में वैश्विक अगुआ बनाया जा सके। (3) 100 दिनों के भीतर विफल राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (जिसमें यूपीए शासन के दौरान बीपीएल परिवारों की कवरेज मात्र 6:रही है) के स्थान पर नया कार्यक्रम शुरू करना। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन का नया कार्यक्रम विशेषाधिकार प्रदान करेगा जो पांच साल के भीतर सभी को इसमें शामिल करने की गारंटी देता है। (4) राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन ऐसे प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास भी शुरू करेगा जिनमें भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

सड़कें : दृष्टिकोण – प्रत्येक भारतीय शहर को जोड़ने के लिए विश्व श्रेणी के राजमार्ग और प्रत्येक भारतीय गांव को जोड़ने के लिए पक्की सड़कें। (1) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के सभी घटकों – स्वर्णिम चतुर्भुज, पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण कॉरिडोरों और जिला राजमार्गों को पूरा करना (2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सन् 2014 से पहले पूरा करना (3) सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों (130,000 प्रतिवर्ष) की संख्या को आधा कम करने हेतु राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मिशन का गठन करना।

रेलवे : दृष्टिकोण – प्रत्येक भारतीय के लिए रेलवे के सफर को आसान, आरामदायक तथा सुरक्षित बनाना और आर्थिक विकास के वाहक के रूप में रेलवे की भूमिका को और सुदृढ़ करना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए (1) सभी लम्बित रेल नेटवर्क विस्तार परियोजनाओ को समयबद्ध तरीके से पूरा करना (2) दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई और कलकत्ता को जोड़ने वाले फ्रेट कॉरिडोरों को समर्पित करना और इन्हें अन्य खनिज तथा औद्योगिक केन्द्रों से जोड़ना। (3) 100 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना (4) भारत के 25 सबसे बड़े शहरों में अर्बन मास ट्रांजिट (मेट्रो रेल) प्रणाली शुरू करना।

बन्दरगाह तथा नौवहन : दृष्टिकोण - भारतीय बंदरगाहों को विश्व के सर्वोत्तम बंदरगाहों की श्रेणी में लाना। इसके लिए (1) भारतीय बंदरगाह और नौवहन आधारभूत ढांचे का व्यापक विस्तार करने तथा उसे आधुनिक बनाने के लिए 'सागर माला' परियोजना शुरू करना (2) कम से कम पांच महत्वपूर्ण मार्गों में अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास करना (3) बंदरगाहों की प्रचालन क्षमता में सुधार लाना ताकि आयात कार्गों को साफ

करने के लिए समय लगने वाले दिनों की औसत संख्या में कमी करके 20 दिनों से 5 दिन करना (4) जहाज निर्माण के लिए भारत को एक बड़ा केन्द्र बनाना।

नागरिक उड्डयन : दृष्टिकोण – हवाई यात्रा को अधिक आसान, अधिक सुविधाजनक तथा अधिक सुरक्षित बनाना। इसके लिए (1) प्रत्येक राज्य की राजधानी तथा महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्र में हवाईअड्डा आधारभूत ढांचे को आधुनिक बनाना (2) एक्सप्रेसवेज, एमआरटी तथा बसों की मदद से शहर से लेकर एयरपोर्ट के बीच आवागमन में सुधार लाना (3) भारत को एयरक्राफ्ट उत्पादन तथा मरम्मत का केन्द्र बनाना।

दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी : दृष्टिकोण - 'इंडिया' में हुए सूचना, संचार और तकनीकी क्रांति के फायदों को 'भारत' तक पहुंचाना। इसके लिए (1) राष्ट्रीय डिजिटल राजमार्ग विकास परियोजना (2) देश के हर छोर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम डिजिटल सड़क योजना (3) हर गांव के लिए केबल टीवी कनेक्शन के दामों पर असीमित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी (4) मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 40 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करना और मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या को बराबर करना (5) ई–भाषा, भारतीय भाषाओं में आईटी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन (6) वैश्विक स्तर पर मुकाबला कर सकने वाले आईटी हार्डवेयर उद्योग का विकास करना जिससे आयात पर निर्भरता कम हो (7) बहु–उद्देशीय राष्ट्रीय पहचान–पत्र बनाने का काम तीन साल में पूरा करना (8) ग्रामीण क्षेत्रों में 1.2 करोड़ आईटी पर आधारित नौकरियां देने की योजना बनाना।

ग्रामीण और कृषि पर आधारित बुनियादी ढांचा : दृष्टिकोण– हमारे गांवों में समृद्धि, खुशहाली और रोजगार के अवसर मुहैया कराना इसके लिए हम पुरा (ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की व्यवस्था) की अवधारणा को मार्गदर्शक मानेंगे (1) किसानों को 24 घण्टे सातों दिन बिजली की आपूर्ति करना (गुजरात में ज्योतिग्राम योजना के माध्यम से ऐसा पहले ही किया जा चुका है) (2) हर गांव को पक्की और सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कें उपलब्ध कराना (3) पीने के साफ पानी और ग्रामीण सफाई की व्यवस्था करना (4) कृषि पर आधारित बाजार (मंडी) के आधुनिकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाना जिसमें बिचौलियों को समाप्त करने के लिए कानूनी सुधार शामिल हैं ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके (5) ग्रामीण इलाकों में अनाज बैंकों, शीत भण्डारों और कृषि प्रोसेसिग ईकाइयों जैसे कृषि में मदद देने वाले आधारभूत ढांचे में व्यापक निवेश लगाना (6) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में इस तरह से सुधार लाना जिससे यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में योगदान दे सके और भ्रष्टाचार खत्म हो सके।

राष्ट्रीय आधारभूत ढांचा प्रोत्साहन और निगरानी एजेंसी (निमा) की स्थापना और १०० श्रीधरनों का सशक्तिकरण :

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के स्पष्ट जनादेश के साथ 90 के दशक में स्थापित एफआईपीबी की तर्ज पर एक उच्च शक्ति–प्राप्त राष्ट्रीय आधारभूत ढांचा प्रोत्साहन और जांच एजेंसी (निमा) गठित करेगा। 'निमा' में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की सर्वोत्तम प्रतिभाओं को सार्वजनिक और निजी भागेदारी की भावना से शामिल किया जाएगा। यह राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं और अन्य परियोजनाओं की प्रगति के बारे में तिमाही जानकारी राष्ट्र को देगा। 'निमा' प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगी।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन मानती है कि आधारभूत ढांचे के विकास के लिए निर्णायक, परिणामकारी और प्रेरक नेतृत्व की जरूरत है। भारत के पास विशाल प्रबंधन प्रतिभा मौजूद है। दुर्भाग्यवश, हमारे प्रबंधकों को शायद ही स्वायत्तता और अपेक्षित शक्ति स्पष्ट जवाबदेही के साथ मिलती है ताकि वे अपना सही लोहा मनवा सकें। जब कभी एक सही प्रबंधक को सही परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सही अधिकार दिए जाते हैं तो हमें आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं। दिल्ली मेट्रो के श्री ई.श्रीधरन का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। लेकिन ऐसे अनेक और भी लोग हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन ऐसे वातावरण का निर्माण करेगा जिसमें शीर्ष स्तर के प्रबंधकों का सशक्तिकरण किया जाएगा जो 100 श्रीधरनों को सामने ला सकें ताकि वे ''कुछ करके दिखा सकें''।

आधारभूत ढांचे के विकास हेतु वित्त-पोषण : अगले पांच वर्षों के दौरान देश में आधारभूत संरचना संबंधी घाटे में बड़ी कमी करने के लिए अनुमानित 25,00,000 करोड़ रूपये अथवा 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की जरूरत है। यद्यपि इतनी धनराशि जुटाना एक दुस्साध्य कार्य नजर आता है। फिर भी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन विदेशों के टैक्स हेवन्स में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से जमा भारतीय धन को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस धनराशि को हमारे देश के आधारभूत ढांचे के विकास में इस्तेमाल किया जाएगा। भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार (जो अभी 247.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है) का भी आधारभूत ढांचा विकास को वित्त–पोषित करने में इस्तेमाल किया जाएगा।

राष्ट्रीय समन्वित शहरी नवीनीकरण मिशन : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन के कवरेज को चार शहरी नवीनीकरण मिशनों में बांटेगा और उसका व्यापक विस्तार करेगा :

- जवाहरलाल नेहरू मेट्रो नवीनीकरण मिशन (10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले लगभग 40 शहरों के लिए)
- सरदार वल्लभभाई पटेल जिला केन्द्र नवीनीकरण मिशन (जवाहरलाल नेहरू मेट्रो नवीनीकरण मिशन में शामिल किए गए शहरों को छोड़कर 600 से अधिक सभी जिला कस्बों के लिए)
- नेताजी बोस तहसील कस्बा नवीनीकरण मिशन (4000 से अधिक सभी तालुका कस्बों के लिए)
- पवित्र भारत तीर्थस्थान नवीनीकरण मिशन (सभी धर्मों के तीर्थस्थानों के लिए)

पांच वर्षों में कम से कम 15 भारतीय शहरों को विश्व स्तर के शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा जहां विश्व श्रेणी के हवाई अड्डे, कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, उच्च कोटि का सामाजिक आधारभूत ढांचा, एक सक्रिय सांस्कृतिक जीवन, और सशक्त वैश्विकसम्पर्कों सहित आर्थिक विकास का एक सक्रिय माहौल होगा। आयोजना और बुनियादी ढांचे के भावी मानकों के आधार पर कम से कम 10 नए शहरों का विकास किया जाएगा। ■

कांग्रेस पार्टी अपने स्वयं के मकड़जाल में फंसी : अरुण शौरी

भाजपा सांसद श्री अरूण शौरी द्वारा 19 अप्रैल, 2009 को नई दिल्ली में जारी प्रेस वक्तव्य

Hkkरत से लूटी गई धनराशि को वापस लाए जाने की मांग को देशभर से मिले भारी समर्थन से सुन्न हुई कांग्रेस पार्टी ने अपने आपको कई गुत्थियों में उलझा लिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बारे में 5 प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं:

- श्री आडवाणी जी चुनावों की पूर्व संध्या पर इस मामले को अब क्यों उठा रहे हैं?
- जीई–20 बैठक इस मुद्दे को उठाने के लिए उचित मंच नहीं था।
- धनराशि के आंकड़ों के बारे में संदेह है।
- भाजपा सरकार ने फेरा की जगह फेमा क्यों लागू किया तथा इसके द्वारा अपराधों को शमनीय क्यों बनाया?
- क्या आडवाणी जी अवैध धन रखने वाले लोगों को स्विटजरलैंड से किसी अन्य Tax Havens पर उड़ा ले जाने के लिए अनजाने में चौकन्ना तो नहीं कर रहे हैं?
- जब राजग सत्तारूढ़ था तब वह इस बारे में क्या कर रहा था? हर स्थिति में आंकड़ों के बारे में संदेह बना हुआ है। ये प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की हड़बड़ाहट दर्शाती हैं, क्योंकि इस पर थोड़े से भी चिंतन–मनन से वह स्थिति सामने आ जाएगी, जिसका बचाव नहीं हो सकता है।
- "श्री आडवाणी जी चुनावों की पूर्व संध्या पर इस मामले को अब क्यों उठा रहे हैं?"

सच्चाई यह है कि आडवाणी जी ने प्रधानमंत्री जी को गत वर्ष अप्रैल में पत्र लिखकर इस मामले को उठाया था। वित्त मंत्री द्वारा उन्हें भेजे गए उत्तर में दर्शाया गया था कि सरकार का सिवाय कुछ कदम उठाने का बहाना करके इस बारे में कुछ भी करने का इरादा नहीं था। इसके कुछ दिन बाद हम यह जानकर चौके कि वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने तत्कालीन जर्मनी–स्थित भारतीय राजदूत को लिखा कि वे जर्मनी द्वारा लीशटैन्सटीन से प्राप्त सूची में भारतीयों के नाम उजागर किए जाने पर जोर न डालें, कहीं ऐसा न हो कि जर्मन इस बात का बुरा मान जाएं और यह निष्कर्ष निकाल लें कि उन पर दबाव डाला जा रहा है और उनकी ईमानदारी पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। (बाद में इस सूचना की पुष्टि इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 31 मार्च, 2009 को प्रकाशित रिपोर्ट से हुई)।

अब क्यों? इसका उत्तर यह है कि पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के गंभीर संकट में फंसे होने के बाद ऐसा करने का नायाब अवसर केवल अभी आया था। इस आर्थिक संकट ने जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और यूके जैसे देशों को मजबूर

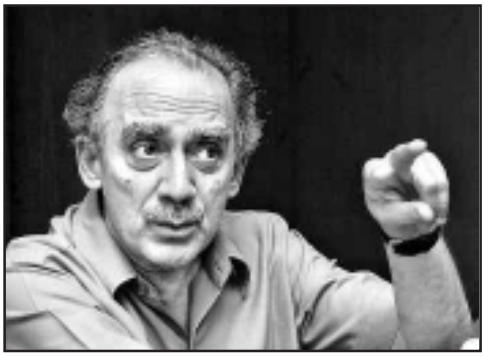

किया था कि वे जी–20 में नेतृत्व की भूमिका ग्रहण करें और Tax Havens से चोरी किए गए धन को वापस लाने की प्रतिज्ञा करें। भाजपा का विश्वास है कि भारत के लिए अपने धन को वापस लाने के लिए वैश्विक प्रयास में शामिल होने का यह उचित समय है।

'जीई-२० बैठक इस मुद्दे को उठाने के लिए उचित मंच नहीं था'

ऐसा आत्म–सेवी युक्तिकरण रिवाजी तौर पर कांग्रेस पार्टी के एक अधिवक्ता और प्रवक्ता द्वारा सुझाया गया था। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी छुपे–छुपे ऐसा संकेत देने का प्रयास भी कर रही थी कि वस्तुतः प्रधानमंत्री ने जी–20 शिखर बैठक में यह मामला उठाया था। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रधानमंत्री द्वारा शिखर बैठक में अथवा शिखर बैठक के बाद हुई "प्रेस मीट" (Press Meet) में दिए गए ऐसे किसी बयान का संकेत नहीं दे सके तब उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर गोर्डन ब्राउन द्वारा दिए गए डिनर के मौके पर प्रधानमंत्री के भाषण में इस मामले का पासिंग रैफरेंस देकर संतोष प्राप्त कर लिया।

किसी भी तरह, यदि जी–20 शिखर सम्मेलन यह मामला उठाने के लिए उचित मंच नहीं था, तब जी–20 नेताओं ने 2 अप्रैल, 2009 को जारी विज्ञप्ति में पैरा 15 में "वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने" के बारे में ऐसा कैसे कहा था कि वे असहयोगी क्षेत्राधिकारों जिनमें Tax Havens शामिल है के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए कृतसंकल्प है। हम अपने सार्वजनिक वित्त और वित्तीय प्रणालियों को संरक्षित रखने के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। बैंकिंग गोपनीयता का युग समाप्त हो चुका है। हमने नोट किया है कि ओईसीडी (OECD) ने आज उन देशों की सूची प्रकाशित की है, जिनको ग्लोबल फोरम ने कर सूचना के विनिमय हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विरूद्ध पाया था?" क्या कांग्रेस पार्टी की नजर में शिखर सम्मेलन के अवसर पर अपनी विज्ञप्तियों में दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त करते समय वे भी अनुपयुक्त रूप में कार्य कर रहे थे?

'धनराशि के आंकड़ों के बारे में संदेह है'

जैसाकि कांग्रेस पार्टी की प्रथा रही है वह उस धनराशि के बारे में जो भारत से लूटी गई है और Tax Havens में पड़ी हुई है, मूल प्रश्न पर आंकड़ों और अनुमानों की परिशुद्धता के बारे में प्रश्न उठाकर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। यह उसी तरह की विधिकवाद है, जिसको अपनाकर मिस्टर पी. चिदम्बरम और अन्य वैधीकरण करने वाले व्यक्तियों ने बोफोर्स से हुई लूट पर पर्दा डालने के लिए प्रयास किया था।

ओईसीडी ने स्वयं अप्रैल 2009 के शुरू में प्रकाशित लेखों–जोखों में उल्लेख किया था कि 1.7 ट्रिलियन से लेकर 11.5 ट्रिलियन डॉलर की धनराशि है, जो आज भी Tax Havens में कैद है। ओईसीडी के इस अनुमान को भारतीय प्रेस में व्यापक रूप से प्रचारित किया था। मूल बिन्दू यह है : चाहे धनराशि कोड़ियों बिलियन डॉलरों में हो, न कि आधा ट्रिलियन डॉलर में हो, फिर भी उसको भारत वापस क्यों नहीं लाया

जाना चाहिए? क्या उस धनराशि को ऐसे में भारत वापस लाया जा सकता है जब सरकार का रवैया पूरी तरह निकम्मेपन से भरा हुआ हो जैसाकि वर्तमान सरकार का है।

क्या जिस सरकार ने इटालवी, सत्ता दलाल, ओटैवियो क्वात्रोची, जो बोफोर्स घोटाले में प्रमुख अभियुक्त है को धनराशि फ्रीज़ कर दिए जाने के बाद भी बैंक से बाहर ले जाने की अनुमति दे दी थी उस पर लूट की राशि जो स्विस बैंकों तथा अन्य Tax Havens पर जमा है, वापस लाने के लिए भरोसा किया जा सकता है? क्या उस सरकार पर जिसने सीबीआई का क्वात्रोची के अर्जेन्टीना से बाहर जाने के लिए दुरूपयोग किया था, लूट की राशि को वापस लाने का भरोसा किया जा सकता है।

'भाजपा सरकार ने फेरा की जगह फेमा क्यों लागू किया तथा इसके द्वारा अपराधों को शमनीय क्यों बनाया?'

पुनः, कांग्रेस पार्टी अपने श्रोतागण की थोड़े समय की याददाशत पर निर्भर हो रही है। मामले की सच्चाई यह है कि फेरा के कठोर उपबंधों को बदलने के लिए कांग्रेस से अधिक कोई पार्टी जोर नहीं डाल रही थी। इन परिवर्तनों पर 1996 से विचार किया जा रहा था। कठोर उपबंधों को दूर किए जाने की मांग सबसे अधिक तेज श्री वी.पी. सिंह की सरकार के दौरान हुई थी जब कठिन परिस्थितियों में उद्योगों के मालिकों से पूछताछ करने के लिए फेरा का प्रयोग किया गया था। जैसा कि उस समय की समाचार रिपोर्ट स्वयं दर्शाती है, फेमा का प्रारूप, जिसे सरकार ने जुलाई 1998 में अनुमोदित किया था, उन्हीं बिन्दुओं के अनुसार तैयार किया गया था, जिन्हें पूर्ववर्ती वित्त मंत्री मिस्टर पी. चिदम्बरम के नेतृत्व में तैयार किया गया था।

निम्नलिखित पैराओं में कानून को बदलने के कारणों को स्पष्ट रूप में उल्लिखित किया गया है:

"हाल ही तक हमारे यहां फेरा के नाम से ज्ञात कानून मौजूद था। इसका उद्देश्य देश की विनिमय मुद्रा रिजर्व को संरक्षित और प्रोत्साहित करना था। कहा जाता है कि स्वर्ग का रास्ता अच्छे इरादों के साथ प्रशस्त होता है। अनेक अच्छे इरादों के साथ तैयार किए गए कानूनों की तरह फेरा से कठिनाईयां पैदा हुई। फेरा ने विदेशी मुद्रा में कालाबाजार की वृद्धि को हवा दी। फेरा ने आर्थिक शब्दकोष में नया शब्द 'हवाला' जोड़ दिया है।" अवैध विदेशी मुद्रा लेन–देनों ने सीमापार संबंध रखने वाले क्राइमस इंडिकेट को बढ़ाने में योगदान किया है।

"फेरा उत्पीड़न का साधन भी बन गया है। उत्तरोतर सरकारों ने फेरा को बनाए रखा तथा कोफेपोसा (COFEPOSA) और सैफेमा (SAFEMA) को अलग से जोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार उन कड़े कानूनों का मान नहीं करते जो सामान्य समझ के विरूद्ध होते है। भारत की रिजर्व विदेशी मुद्रा बढ़ने की बजाय चिंताजनक दर पर कम हो गया। अच्छी बात यह हुई कि 31 मई 2000 को फेरा को अंतिम रूप से दफन कर दिया गया।

लेखक कौन था? मिस्टर पी. चिदम्बरम के अलावा कोई और नहीं था, जिन्होंने 25 अगस्त, 2002 को इंडियन एक्सप्रेस में उक्त लेख लिखा।

'क्या आडवाणी जी अवैध धन रखने वाले लोगों को स्विटजरलैंड से किसी अन्य Tax Havens पर उड़ा ले जाने के लिए अनजाने में चौकन्ना तो नहीं कर रहे हैं?'

कांग्रेस पार्टी के अन्य अधिवक्ता द्वारा दिया गया अन्य चतुराईभरा बयान। क्या उन लुटेरों को जिन्होंने भारत की धनराशि Tax Havens पर छिपा दी है। उसके बाद भी सतर्क किए जाने की जरूरत है जब जर्मनी ने उनके नाम लीशटेन्सतिन से पिछले वर्ष ही प्राप्त कर लिए थे। क्या उन्हें उसके बाद फिर भी सतर्क किए जाने की जरूरत है जब जर्मनी ने नाम चाहने वाली सरकार को नाम बनाते की पेशकश की थी? क्या उन्हें इसके बाद भी सतर्क किए जाने की जरूरत थी।

जब अमेरिका ने इस वर्ष फरवरी में उनके नाम स्विटजरलैंड के प्रमुख बैंक यूबीएस से प्राप्त कर लिए थे। क्या उन्हें उसके बाद भी सतर्क किए जाने की जरूरत थी जब डॉ. मनमोहन सिंह सहित जी–20 के नेताओं ने Tax Havens से उनके नाम प्राप्त करने का संकल्प व्यक्त किया था। किन्तु कांग्रेस पार्टी में ऐसा भ्रम व्याप्त है और इसके अधिवक्ता इतने प्रतिभाशाली है, वे देशभर से उठ रही लूट की राशि को जंग भ्अमदे से वापस लाने की मांग को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं।

'जब राजग सत्तारूढ़ था तब वह इस बारे में क्या कर रहा था? हर स्थिति में आंकड़ों के बारे में संदेह बना हुआ है'

अच्छा होगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता पूछें कि राजग सरकार के उन लोगों के नाम उजागर करने के प्रयासों को जिन्होंने बोफोर्स जैसे रक्षा सौदों तक में देश को लूटा था, निष्फल करने के लिए उस दौरान कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, इसके नेता, अधिवक्ता क्या कर रहे थे?

फेरा की जगह फेमा लाते समय भी राजग सरकार ने सुनिश्चित किया था कि फेरा के अधीन अभियोजन फाइल करने के लिए दो वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा और उसने ऐसे लोगों के विरूद्ध 2000 केस फाइल किए थे, जिसमें फेरा के व्यपगत होने से पहले पूछताछ की जा रही थी। ऐसा करने का कारण – वह कारण जो कांग्रेस पार्टी के अधिवक्ताओं को अच्छी तरह ज्ञात था – यह था कि जब कोई अभियोजन फाइल किया जाता है तब उसे समकालीन कानून के अनुसार नयायनिर्णीत किया जाता है। ये वे ही हैं, जिनकी कांग्रेस पार्टी ने बाद में पैरवी नहीं की।

निष्कर्ष

vlyh yMkbZ vkx gS % वह लड़ाई जो देश के हित में है, वह लड़ाई जिसे उन लोगों के नाम जानने के लिए लड़ा जाना है, जो Tax Havens में दर्ज हैं और वह लड़ाई जिसे लूटे हुए धन को वापस लाने के लिए लड़ा जाना है।

जैसा कि श्री आडवाणी ने जोर देकर कहा है देशभर में सर्वानुमति बन रही है। अनय राजनीतिक दलों जैसे जद(यू), एआईडीएमके, सीपीआई(एम), एसपी और बीएसपी के नेताओं ने भी मांग की है कि सरकार Tax Havens से उन लोगों के नाम प्राप्त करने के लिए और धनराशि वापस लाने के लिए शिद्दत से प्रयास करे।

इधर–उधर के बहाने करने के बजाय कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि उसने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जबकि जर्मनी की सरकार ने उन लोगों के नाम बताने की पेशकश की थी, जो उसने स्वयं प्राप्त किए थे।

श्री आडवाणी ने अब भी कांग्रेस सहित सभी पार्टियों से आग्रह किया है कि वे मिलकर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करें।

यह वही उद्देश्य है, जिसको पुनः सत्ता मिलने पर राजग प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम करेगा।■

सीबीआई राजनीति का खिलौना बनती जा रही है

f'ko'kfDr cD'kh

कांग्रेस ने भले ही लोगों में फैले व्यापक आक्रोश के कारण श्री जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार को लोकसभा का चुनाव लड़ाने का निर्णय बदल दिया हो, परन्तु इससे सीबीआई ने जिस प्रकार से जांच कार्य किया है, उससे वह इस प्रकरण से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकती है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब सीबीआई सार्वजनिक रूप से अपनी आरोपित निष्पक्ष भूमिका के लिए कठघरे में खड़ी हो गई है और उसे अपमानित होना पड़ा है।

विश्वसनीयता की कमी के कारण आज सीबीआई को एक दब्बू, अक्षम और पूर्वाग्रह से ग्रसित एजेंसी माना जाता है जिसे कभी भी राजनैतिक रूप से डरा–धमका कर उसके निर्णय को परिवर्तित किया जा सकता है। जिस प्रकार से सिखों के खिलाफ 1984 में कांग्रेस द्वारा भड़काए गए दंगों से सम्बन्धित मामले में जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दी गई, उससे उसकी बची–खुची विश्वसनीयता भी गड्ढे में जा गिरी है। ऐसा लगता है कि जैसे पहले से ही सब कुछ 'स्टेज मैनेज' किया हुआ था। पहले तो सीबीआई ने किसी विश्वसनीय साक्ष्य न होने के कारण न्यायालय के सामने आवेदन किया और फिर, सीबीआई के अनुरोध पर न्यायालय से आदेश देने की बात कही तो कांग्रेस ने दिल्ली से टाइटलर को लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में नामित कर दिया। इससे पहले भी, सीबीआई ने अपने 29 सितम्बर के आरोपपत्र में दावा किया था कि जसबीर सिंह, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने टाइटलर को सिखों की हत्या करने के लिए भीड़ को उकसाया था, उसकी जांच पड़ताल नहीं की जा सकती है क्योंकि वह अमरीका में जा बसा है और उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। सीबीआई के इस दावे की तुरंत ही पोल खुल गई क्योंकि मीडिया ने टेलीफोन से जसबीर सिंह का पता–ठिकाना मालूम कर लिया था। टाइटलर को जिस प्रकार से जानबूझ कर बचाने का प्रयास किया गया, वह इस बात से सिद्ध है कि सीबीआई ने जैन–अग्रवाल समिति और नानावती आयोग को दिए गए जसबीर सिंह के साक्ष्य को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। अब जब न्यायालय ने इस मामले की पुनः जांच के आदेश दिए तो सीबीआई ने कहा कि जसबीर सिंह के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इसलिए उसने न्यायालय से मामले को बंद करने का अनुरोध किया। गृहमंत्री पी. चिदम्बरम पर एक पत्रकार द्वारा जूता फेंकने की घटना से हुए हंगामे के कारण सीबीआई को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

सीबीआई स्वयं को ऐसा राजनैतिक उपकरण बनाती जा रही है जो सत्ता में बैठे लोगों के लिए सहयोगी दल ढूंढने में लगी है और जो यूपीए का भण्डा फोडने के लिए खतरा बन गए है, उन्हें दण्डित करने का बीडा उठा रखा है। यूपीए सरकार द्वारा सीबीआई का दुरूपयोग करने के कारण सीबीआई की विश्वसनीयता को भारी धक्का लगा जो कभी उच्च क्षमता और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम करती थी और जिस पर कोई राजनैतिक प्रभाव नहीं पड़ सकता था।

और भी बहुत से मामलों में सीबीआई शक के दायरे से बाहर नहीं है। हाल ही में पूरे देश को उस समय गहरा विक्षोभ और आघात लगा जब निठारी हत्याकांड के प्रमुख आरोपी मोहिन्दर सिंह पंढ़ेर को लगभग बरी कर दिया गया था। न्यायालय को सीबीआई को आदेश देना पड़ा था कि जो पहले ही निर्णायक और अकाट्य साक्ष्य हैं, उनके आधार पर जांच के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। बच्चों की हत्या के मामले में सीबीआई–जांच जिस अक्षम ढंग से की गई, उससे सीबीआई के प्रोफेशनिलिज्म और उसकी अक्षमता का पता चल जाता है। मामले की पुनः जांच पर न्यायालय ने पंढ़ेर को दोषी करार दिया।

इसके अलावा भी, न्यायालय के दो प्रमुख निर्णय हैं जिससे सीबीआई के कामकाज की स्थिति पर गहरी चिंता होती है। बोफोर्स के अभियुक्त ओत्तावियों क्वात्रोच्चि को अर्जेंटाइना की अल–डोरेडो कोर्ट ने बरी कर दिया और एक हत्या के मामले में सेशन कोर्ट ने शिबू सोरेन के निजी साहयक की हत्या में बरी कर दिया गया। इन दो मामलों पर पूरे राष्ट्र का ध्यान था। शिबू सोरेन के मामले में कानूनी कार्रवाई, जटिलताओं के घेरे में रह कर ऐसा लगता है इस मामले में 'न्याय में देरी होने से इंसाफ नहीं हो पाता है' सिद्ध नहीं होती है, परन्तु जिस प्रकार का घटनाक्रम चला, इससे फिर से सीबीआई के कामकाज करने के तरीके पर आंच आती ही है।

बोफोर्स मामले में दलाली के आरोप में क्वात्रोच्चि को रेड कार्नर इंटरपोल नोटिस पर अर्जेंटाइना में गिरफ्तार किया गया था। पूरे देश को उसकी गिरफ्तारी की खबर से अंधेरे में रखा गया और जब किसी तरह से यह खबर मीडिया में आई, सीबीआई ने उसके प्रत्यर्पण की बात नहीं की। क्वात्रोच्चि के प्रत्यर्पण के लिए सीबीआई के प्रयास का पता उस समय खुल कर सामने आया जब सीबीआई ने 'लोवर कोर्ट' में हारने के बाद सीबीआई ने इसके खिलाफ अर्जेंटाइन सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं

....पृष्ठ 27 पर शेष

राजग ही देश को नई दिशा देने में सक्षम : लालकृष्ण आडवाणी

Hkkजपा के वरिष्ठ नेता और राजग के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री लालकृष्ण आडवाणी देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर जमकर चुनाव–प्रचार कर रहे हैं। वे अब तक सैकड़ों चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं और उनका यह अभियान जारी है। जनसभाओं में मिले प्रतिसाद से वे खासे उत्साहित हैं और वे दावा करते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा इकलौती सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आएगी। अपने संबोधन में वे लोगों से जाति, परिवार और व्यक्ति पर केंद्रित पार्टियों को सबक सिखाकर राष्ट्रहित का ध्यान रखने वाली भाजपा को समर्थन देने की अपील करते हैं। उनका कहना है कि राजग की सरकार बनने पर आम आदमी को उसका पूरा हक और सम्मान दिया जाएगा।

गत 11 अप्रैल को **बक्सर, सासाराम** और **नवादा(बिहार)** में आयोजित चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए श्री आडवाणी ने कहा कि केंद्र में राजग के सत्ता में आने पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा और ऐसी नीति बनाई जाएगी जिसमें आतंकवाद और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। श्री आडवाणी ने कहा कि केंद्र में सत्ता में आने पर करों की चोरी करने वालों की ओर से दूसरे देशों के बैंकों में जमा किए गए अकूत धन को राजग देश में वापस लाएगा। बक्सर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। प्रदेश की नीतीश सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों की श्री आडवाणी ने जमकर तारीफ की।

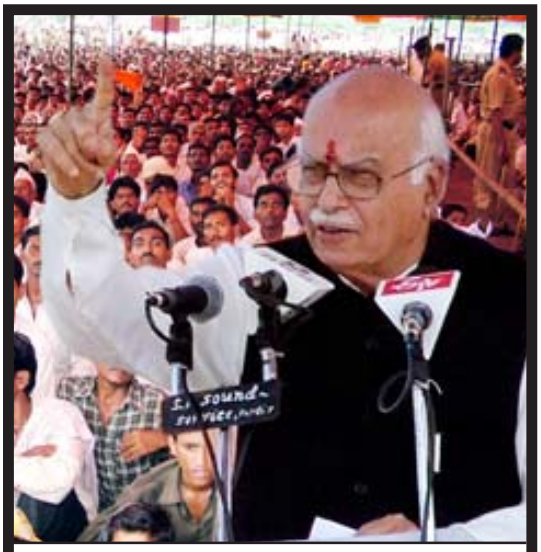

जाति, परिवार और व्यक्ति पर केंद्रित पार्टियों को सबक सिखाकर राष्ट्रहित का ध्यान रखने वाली भाजपा को समर्थन दें। राजग की सरकार बनने पर आम आदमी को उसका पूरा हक और सम्मान दिया जाएगा।

कवर्धा(छत्तीसगढ़) में 11 अप्रैल को आयोजित एक रैली में श्री लालकृष्ण आडवाणी ने एनडीए सरकार आने पर ई–गवर्नेंस देने का वायदा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ई–गवर्नेंस की शुरुआत अपने शासन वाले प्रदेशों से पहले ही कर दी है। छत्तीसगढ़ में सस्ता चावल इसका उदाहरण है। सभा में मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह ने कहा कि यूपीए शासन के पिछले पांच सालों में छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय हुआ है।

तिरुअनंतपुरम्(केरल) में 14 अप्रैल को चुनाव–प्रचार के दौरान जनसभा में श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के उस बयान पर उनसे माफी मांगने की मांग की जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को विदेशी आतंकवादियों की अपेक्षा देश के अंदर के लोगों से ज्यादा खतरा है। श्री आडवाणी झारखंड रैली के दौरान सोनिया गांधी के बयान का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने सोनिया गांधी के बयान को तथ्य से मुंह मोड़ने वाला बताते हुए कहा कि 1962 और 1965 के युद्ध के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री ने भी जनसंघ और आरएसएस की भूमिका की सराहना की थी। यहां तक कि वर्ष 1963 में एक विरला उदाहरण पेश करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान आरएसएस से एक दल भेजने को कहा था।

लखनऊ (उत्तरप्रदेश) में 19 अप्रैल को श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि राजग सरकार बनने पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने का सपना साकार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में राममंदिर न बना तो करोड़ों देशवासियों की मुराद अधूरी रह जाएगी।

टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) में 22 अप्रैल को एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा भाजपा के नेतृत्व वाला राजग ही देश को नई दिशा देने में सक्षम है।

श्री आडवाणी ने राजग की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 1998 में केन्द्र में राजग सरकार बनने के कुछ माह बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बनाने का निर्णय किया और पोकरण में परमाणु परीक्षण कर इस पर अमल भी करके दिखा दिया। इस उपलब्धि से भारत का सम्मान दुनिया में बढा है। ■

कड़े कदम उठाने का कांग्रेस में दम नहीं : राजनाथ सिंह

Hkkजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार की कमजोरी से पाक आतंकी ठिकानों को तबाह करने में कोताही बरती जा रही है। लेकिन केन्द्र में जब भाजपा और एनडीए सरकार थी तब आतंकियों के हौसले पस्त हो गए थे।

गत 9 अप्रैल को श्री राजनाथ सिंह ने **वाराणसी** लोकसभा क्षेत्र के चंदौली, बलिया, मिर्जापुर, आजमगढ़ जनपदों में आयोजित चुनावी जनसभाओं में बसपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अदूरदर्शिता के चलते गंभीर संकट से गुजर रहा है। अपराध का सबसे ऊंचा ग्राफ उत्तर प्रदेश का है। उन्होंने कहा कि किसान व बुनकरों की बदहाली की जिंदगी के लिए कांग्रेस व बहुजन समाज पार्टी जिम्मेदार है। मायावती सरकार की दिग्भ्रमित नीतियों के कारण किसान की खेती गंभीर समस्या से जूझ रही है साथ ही आर्थिक क्षति भी हो रही है।

केन्द्र सरकार की कमजोरी से पाक आतंकी ठिकानों को तबाह करने में कोताही बरती जा रही है। लेकिन केन्द्र में जब भाजपा और एनडीए सरकार थी तब आतंकियों के हौसले पस्त हो गए थे।

छपरा(बिहार) में 14 अप्रैल को श्री राजनाथ सिंह ने देश में महंगाई समेत सभी समस्याओं के लिए कांग्रेसनीत संप्रग को जिम्मेवार ठहराते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण ही आम आदमी हर ओर से त्रस्त है। श्री सिंह ने सारण लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी के समर्थन में हुई एक चुनावी सभा में कहा कि देश में जब भी कांग्रेस या कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी है, महंगाई अपने चरम पर पहुंची है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती राजग सरकार की चर्चा करते हुए कहा कि राजग शासनकाल में सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें काफी कम थी। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक सांप्रदायिक पार्टी है क्योंकि आजादी के बाद सबसे लंबे अरसे तक सत्ता में रही कांग्रेस की नीतियां, अल्पसंख्यकों के मन में भय और असुरक्षा की भावना पैदा करने वाली थी।

बेंगलुरु(कर्नाटक) में 16 अप्रैल को श्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेसनीत यूपीए को डूबता जहाज व भाजपानीत राजग को मजबूत गठजोड़ करार देते हुए कहा कि जहां राजग दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है वहीं यूपीए डूबता रहा है और इसके सहयोगी दल खुद को बचाने के लिए जहाज छोड़कर कूद रहे हैं। उन्होंने यूपीए सरकार को सभी मोर्चों पर विफल करार देते हुए कहा कि इस सरकार के पांच साल के शासनकाल में देश को अप्रत्याशित संकट से गुजरना पड़ा है। केंद्र में दृढ़ इच्छाशक्ति वाली सरकार व निर्णायक नेतृत्व के अभाव में स्थिति और बिगड़ गयी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार की गलत नीतियों का दंश देश के आम आदमी को झेलना पड़ा। देश की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आकर चरमरा रही है।

जलगांव(महाराष्ट्र) में 19 अप्रैल को श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांगेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को संभल कर बोलना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष ने किसानों की आत्महत्या और आतंकवाद के मुद्दों पर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया। मराठावाड़ा से लेकर उत्तर महाराष्ट्र के कई संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि शरद पवार कृषि मंत्री हैं, लेकिन किसानों की आत्महत्या पर तनिक भी विचलित नहीं होते। आतंकवाद के मामले में भी यही हाल रहा। कांग्रेस ने संसद पर हमले के दोषी अफजल को अभी तक फांसी नहीं दी है।

जौनपुर(उत्तर प्रदेश) में 20 अप्रैल को श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। इसके पांच वर्ष के कार्यकाल में महंगाई, भ्रष्टाचार और गरीबी के साथ ही आतंकवाद भी बढ़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता संभालने के बाद दावा किया था कि दो वर्ष में प्रदेश में खुशहाली और तरक्की आ जाएगी, लेकिन हाल यह है कि राज्य में गुंडे और माफिया प्रभावी हो गए हैं। जातिवाद की राजनीति से ऊब चुका मतदाता इस बार आतंकवाद के खात्मे का मन बना चुका है।

इंदौर(मध्य प्रदेश) में में 22 अप्रैल को श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) बिखर गया है और चुनाव के बाद केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार ही बनेगी। श्री सिंह ने केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेतृत्व वाले संप्रग पर टिप्पणी करते हुए कहा पिछले पांच वर्षों में यह सिद्ध हो गया है कि ये ना कभी संयुक्त था ना प्रगतिशील और ना ही इसमें कभी गठबंधन रहा।■

भय-भूख ही कांग्रेस की उपलब्धि : नरेंद्र मोदी

Hkkजपा के वरिष्ठ नेता व गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कड़े प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि पिछले साठ सालों में से अधिक समय तक सत्ता में रही कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति की और इस देश को भय और भूख के सिवा कुछ नहीं दिया है।

श्री मोदी 9 अप्रैल को **बीजापुर(कर्नाटक)** में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में जहां एक तरफ आतंकवाद तांडव कर रहा है तो दूसरी तरफ महंगाई के कारण गरीबों के बच्चे भूख से तड़पकर मर रहे हैं। गरीबों का दर्द क्या होता है, इसका अहसास कांग्रेस को कतई नहीं है। ऐसे में भला कांग्रेस से गरीबों की भलाई की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने ही बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद सब कुछ भूल गई। श्री मोदी ने कहा कि पिछले साठ सालों के शासनकाल में कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति कर देश को बरबाद ही किया है। वोट बैंक की राजनीति जब तक बंद नहीं होगी, तब तक देश का भाग्य नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि देश में विकास का इतिहास लिखने वाली भाजपानीत राजग सरकार के सत्ता में आने पर देश विकास की राह पर अग्रसर होगा। उन्होंने राष्ट्रवादी नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की।

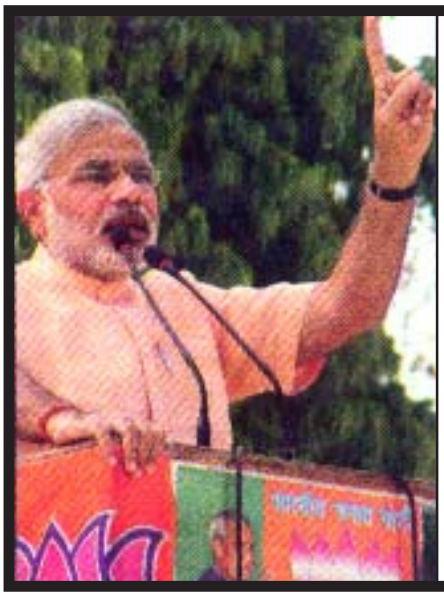

देश में जहां एक तरफ आतंकवाद तांडव कर रहा है तो दूसरी तरफ महंगाई के कारण गरीबों के बच्चे भूख से तड़पकर मर रहे हैं। गरीबों का दर्द क्या होता है, इसका अहसास कांग्रेस को कतई नहीं है। ऐसे में भला कांग्रेस से गरीबों की भलाई की अपेक्षा कैसे की जा सकती है।

बलिया(उत्तर प्रदेश) में 10 अप्रैल को आयोजित एक जनसभा में श्री नरेंद्र मोदी ने वोट–बैंक की राजनीति पर प्रहार करते हुए कहा कि यह राजनीति देश को तबाह व खोखला कर देगी। सपा, बसपा व कांग्रेस एक ही गोत्र के हैं। उत्तर प्रदेश में सपा व बसपा के पनपने के लिए उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सपा व बसपा ने राम व कृष्ण की धरती को गुंडाशाही व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर रौंद डाला है। प्रदेश की जनता कांग्रेस का पाप भुगत रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सपा व बसपा से मुस्लिम वोट–बैंक वापस के लिए सच्चर आयोग की रिपोर्ट लागू की।

वाराणसी(उत्तर प्रदेश) में 11 अप्रैल को श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी को विद्वान व राष्ट्रीय नेता बताया। श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे अलगाववादी ताकतों को हराने के लिए भाजपा को केंद्र की सत्ता सौपें। उन्होंने पोटा कानून को हटाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस अब देश के लिए बोझ बन गई है।

बालासिनोर(गुजरात) में श्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जब भी सत्ता में रही सुरक्षा के मुद्दे पर असहाय दिखी। श्री मोदी ने 13 अप्रैल को खैड़ा जिले के बालासिनोर शहर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 1962 के भारत–चीन युद्ध के समय कांग्रेस क्या कर रही थी। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस तब क्या कर रही थी। आज भी हजारों एकड़ जमीन चीन के कब्जे में है। श्री मोदी ने पूछा आज भी आधा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। यह किस तरह की मजबूती दिखाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री कांग्रेस के असहाय होने के कारण घुटने टेक रहे हैं या यह उनकी आदत है।

पंचमहाल(गुजरात) में आयोजित एक जनसभा में श्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभाजन, चरारे शरीफ, रूबिया प्रकरण से लेकर पाकिस्तान और चीन के साथ युद्धों के मुद्दे उठाते हुए कहा कि कांग्रेस हर मोर्चे पर कमजोर रही। श्री मोदी ने 14 अप्रैल को गुजरात के करीब आधा दर्जन जिलों में चुनाव सभाएं कीं। उन्होंने कहा, कंधार को याद करने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चरारे शरीफ हमले को क्यों भूल गए? वहां जब सेना के जवान लड़ रहे थे तब सरकार आतंकियों को चिकन बिरयानी परोस रही थी। एक दरगाह को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए सरकार सात दिनों तक आतंकियों की सेवा करती रही। श्री मोदी ने कहा, पीडीपी के नेता मुफ्ती मुहम्मद सईद की पुत्री रूबिया के बदले पांच खूंखार आतंकियों को छोड़ा गया। आज वही पीडीपी कांग्रेस के साथ है। ■

कांग्रेस आम आदमी का विश्वास खो चुकी : सुषमा स्वराज

Hkkरतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, झारखण्ड की लोकसभा चुनाव प्रभारी श्रीमती सुषमा स्वराज ने भोपाल में 20 अप्रैल को कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अनुकूल आयेंगे।

उन्होंने विश्वासपूर्वक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में सबसे बडे दल के रूप में उभरेगी और एनडीए अपने बलबूते पर केन्द्र में सरकार बनाएगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि 16 मई के पश्चात हमें लोकसभा के केन्द्रीय कक्ष में साथ–साथ बैठना हैं, इसलिए भाषा की मर्यादा पर इतनी गंभीरता बरती जाए कि हमें आपस में बात करते समय शर्मिंदगी नहीं झेलना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की – कमजोर प्रधानमंत्री– की टिप्पणी व्यक्ति पर नहीं है। यह कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। स्पष्ट रूप से यह कार्य शैली पर टिप्पणी हैं। इस पर न तो उत्तेजित होना चाहिए और न बात का बतंगड़ बताया जाना चाहिए। बहस, राजनीतिक मुद्दों पर हो, तभी यह बहस लोकतंत्र का माध्यम बनेगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने महंगाई के दंश से परेशान जनता की व्यथा पर चिंता व्यक्त की और कहा कि प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और उनकी सरकार मुद्रास्फीति कम होने के आंकड़े परोस रही है। लेकिन आंकडों से आम आदमी का पेट नहीं भरता है। आम आदमी के नाम पर कांग्रेस सत्ता में आई थी। लेकिन उसके शासन में आम आदमी ही सबसे अधिक शोषित, पीड़ित और परेशान हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस को आम आदमी क्यों वोट देगा, कांग्रेस तो आम आदमी का विश्वास खो चुकी है।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि इस चुनाव में यूपीए सरकार की विफलताएं मुद्दा हैं। देश का मतदाता कांग्रेस से हताश हो चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले मतदान चरणों में जहां चुनाव हुए हैं और मत प्रतिशत गिरने की बात सामने आई है, उसका एक मात्र कारण यही है कि कांग्रेस से लोग निराश हुए हैं और उनकी उदासीनता कम मतदान के रूप में परिलक्षित हुई हैं। ■

पृष्ठ 23 का शेष

की। 2005 में भी क्वात्रोच्चि को दलाली के पैसे को बैंक से निकालने दिया गया जब यूपीए सरकार ने ब्रिटिश अधिकारियों को उनके 21 करोड़ के खाते को 'डिफ्रीज' करने दिया गया था। जिस ढंग से सीबीआई ने क्वात्रोच्चि के मामले की जांच पड़ताल की है उसमें अभियुक्त की मदद करने की मंशा साफ दिखाई पड़ती है और सीबीआई ने जानबूझ कर राजनैतिक रूप से अपना दुरूपयोग होने दिया। उसने अभी तक भी अभियुक्त को देश में लाने के लिए कोई भी अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली के जिला न्यायालय ने झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष को उनके निजी सचिव शशिनाथ झा के अपहरण और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 22 अगस्तर 2007 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें अपहरण और हत्या के आरोप से बरी कर दिया। निचली अदालत के निर्णय को 'ओवर रूल' करते हुए उच्च न्यायालय ने सोरेन के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाने में असफल होने के कारण सीबीआई की गहरी निंदा की थी। परन्तु उच्च न्यायालय ने सोरेन की सजा को खारिज किए जाने पर सभी हक्के–बक्के रह गए थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सीबीआई इतनी अधिक अकुशल है कि वह किसी भी प्रकार के राजनैतिक दबाव में आ जाती है। यह भी आश्चर्य और स्पष्ट बात है कि केन्द्र में यूपीए सरकार को जीवनदान देने के लिए सीबीआई ने हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील तक नहीं की।

हम देखते हैं कि टाइटलर–क्वात्रोच्चि सोरेन प्रकरण सीधे–सीधे सीबीआई को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं तो उधर दूसरी तरफ पंढेर का मामला पूरी व्यवस्था की बीमारियों का पर्दाफाश कर रहा है। मायावती, मुलायम सिंह, लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई की असफलता आए दिन उसका उपहास उड़ा रही है। सीबीआई स्वयं को ऐसा राजनैतिक उपकरण बनाती जा रही है जो सत्ता में बैठे लोगों के लिए सहयोगी दल ढूंढने में लगी है और जो यूपीए का भण्डा फोडने के लिए खतरा बन गए है, उन्हें दण्डित करने का बीडा उठा रखा है। यूपीए सरकार द्वारा सीबीआई का दुरूपयोग करने के कारण सीबीआई की विश्वसनीयता को भारी धक्का लगा जो कभी उच्च क्षमता और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम करती थी और जिस पर कोई राजनैतिक प्रभाव नहीं पड़ सकता था। अब यह संस्था एक मखौल बनकर रह गई है जिससे उम्मीद की जाती थी कि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करेगी। राजनैतिक निहित स्वार्थ साधने के लिए यूपीए ने उन उच्च आदर्शों को ताक पर रख दिया है जिसके लिए सीबीआई का गठन हुआ था। यूपीए की तात्कालिक राजनैतिक और चुनावी हितों को साधने के उद्देश्य से सरकार की अल्पकालिक दृष्टि से सीबीआई से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। दीर्घकाल में इस प्रकार के दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक राजव्यवस्था मूल्यहीन बन जाएगी और यह महत्वपूर्ण संस्था बार–बार राजनैतिक दुरूपयोग के कारण बेकार बन जाएगी। यही अवसर है जब हमें साहसी सुधारवादी उपाए अपना कर सीबीआई जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता को बहाल करना होगा।■

आर्थिक संकट से मुक्ति के लिए एनडीए को जिताये : प्रो. कोहली

Hkkजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली ने 14 अप्रैल को दिल्ली की जनता का आह्वान किया कि वे स्थिर, निर्णायक एवं मजबूत सरकार के लिए भाजपा प्रत्याशियों को जिताएं तथा श्री लालकृष्ण आडवाणी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं।

प्रो. कोहली ने कहा कि इस बार सबसे बड़ा खतरा यह है कि यदि केन्द्र में भाजपा की सरकार नहीं बनती तो देश भीषण अराजकता के दौर में चला जाएगा क्योंकि भाजपा के अलावा जितने भी दल देश में हैं उनके पास एक दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री पद के दावेदार मैदान में ताल ठोंक रहे हैं।

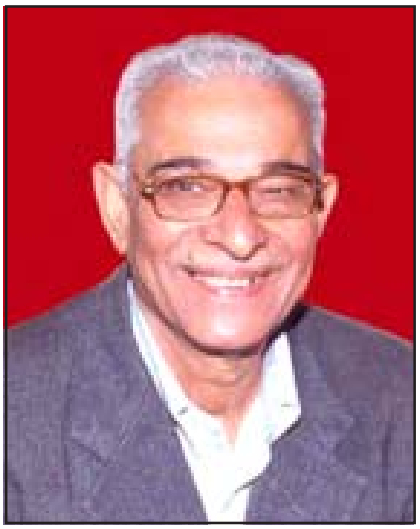

इनमें 19 सीट से लेकर 39 सीट वाले भी दलों के मुखिया भी प्रधानमंत्री बनने का दिवास्वप्न देख रहे हैं। देश के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि यदि भाजपा केन्द्र में सत्ता में नहीं आती तो देश को मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ेगा। परिणाम यह होगा कि देश भयंकर आर्थिक संकट में घिर जाएगा।

उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार के पांच वर्षीय शासन को जनता ने देख लिया है। इन पांच वर्षो में महंगाई पांच गुना बढ़ी है। करोड़ों लोग जीविकाविहीन हुए हैं। देश में अंदरूनी एवं बाहरी खतरे बढ़े हैं।

मुम्बई हमलों के बाद संप्रग सरकार ने दावा किया था कि सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद कर ली गई है, परन्तु हाल के असम विस्फोटों, पूर्वोत्तर राज्यों, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कश्मीर आदि की हिंसक घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। आज भी देश अंदरूनी एवं बाह्य खतरों से जूझ रहा है।

प्रो. कोहली ने कहा कि हाल के दिनों में राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में आपराधिक वारदातों में तेजी आई है। अपराधी न केवल सरेआम लोगों को लूट रहे हैं, बल्कि अब वे पुलिस बल पर भी हमले कर रहे हैं। राजधानी में संगठित अपराधी गिरोहों की संख्या बढ़ रही है। चेन खींचने की घटनाएं, कारों का शीशा तोड़कर पर्स, लैपटॉप, स्टीरियो आदि चुराने की घटनाएं आम हैं। ■

गरीब की थाली तीन गुना महंगी: प्रो. मल्होत्रा

भाजपा दिल्ली प्रदेश चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन एवं दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा है कि वर्ष 1998 में प्राकृतिक आपदा के कारण प्याज की कीमतें 16 से 18 रूपए किलो हुई थीं तब कांग्रेस ने मंहगी प्याज को मुद्दा बनाया था और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार हुई थी। आज सिर्फ प्याज ही नहीं घरेलू उपयोग की सभी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री दिल्ली, कांग्रेस अध्यक्षा समेत सम्पूर्ण संप्रग पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं जबकि मंहगाई बढ़ने का कोई भी वाजिब कारण सरकार के पास नहीं है।

प्रो. मल्होत्रा ने बताया कि दो हफ्ते में अचानक चीनी के दाम 19 रूपए से बढ़कर 27 रूपए किलो, प्याज के दाम 12 रूपए किलो से बढ़कर 20 रूपए किलो, टमाटर 10 रूपए से 20 रूपए किलो, अरहर दाल 40 रूपए से बढ़कर 57 रूपए किलो और सरसों का तेल 55 रूपए किलो से बढ़कर 70 रूपए किलो के भाव बिक रहा है। दूध के दाम 11.25 प्रतिशत, अन्य दालें 21 प्रतिशत, यहां तक कि नमक के दाम 17 प्रतिशत बढ़ चुके हैं। दामों में यह बढ़ोतरी अचानक क्यों हुई है, इसका जवाब भाजपा केन्द्र की कांग्रेस सरकार और दिल्ली की कांग्रेस सरकार से चाहती है। सरकार यह ढिंढोरा पीट रही है कि महंगाई लगातार गिर रही है फिर रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम भरपूर उपज के बावजूद क्यों बढ़ रहे हैं, इसका जवाब कांग्रेस को देश की जनता को देना होगा।

उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह की मंहगाई के बारे में जानकारी का आलम यह है कि महिला पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने खुद स्वीकारा है कि उन्हें यह नही मालूम है कि दिल्ली और देश में आटा, दाल, फल, सब्जी, नमक, तेल के भाव क्या हैं। जब देश के प्रधानमंत्री को ही यह न पता हो कि गरीब की थाली तीन गुना महंगी हो गई है तो सरकार कीमतें घटाने के उपाय क्या करेगी?

उन्होंने दिल्ली की जनता का आह्वान किया कि हर हाल में कांग्रेसी प्रत्याशियों को रिकार्ड मतों से हराएं ताकि भाजपा शासन में आए और चीजों के दाम घटें तथा स्थिर हो जायें।■

काहे का विकास, कैसी खुशी
हज़ारों किसानों ने की खुदकुशी.
मौजूदा सरकार ने किसानों से कर्ज़ माफ़ी का वादा तो किया पर 80% किसानों को कुछ नहीं मिला. इसलिए इस सरकार के पिछले पाँच वर्षों के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्याएँ हुई हैं.
हम किसानों के विकास के लिए उनके पुराने सब कर्ज़े माफ़ कर नये कर्ज़े केवल 4% ब्याज पे देंगे.
हम सिर्फ़ वादे नहीं, काम पूरा करने के इरादे रखते हैं.
भाजपा
मज़बूत नेता, निर्णायक सरकार.

मेरी रसोई का खर्च क्यों बढ़ता जा रहा है?
खाने के दाम आसमान छू रहे हैं. रसोई का खर्चा उठाना भी मुश्किल हो गया है पर मौजूदा सरकार फिर भी कह रही है कि महँगाई घटी है.
पाँच साल पहले बीजेपी सरकार ने दामों को काबू में रखा था और वो हम फिर से करेंगे.
हम सिर्फ वादे नहीं, काम पूरा करने के इरादे रखते हैं.
भाजपा
मज़बूत नेता, निर्णायक सरकार.